



RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ.. सच

माही की गूँज

www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-07, अंक - 49

(साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 04 सितम्बर 2025

पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार



जीवन में
सुकून
के लिए
तीन
आदतें -

* थोड़ा सब करना
* थोड़ा बर्दास्त करना
* थोड़ा नजरअंदाज करना
गौर गोपाल दास

आखिर राजनीतिक बयान बाजी का स्तर इतना क्यों गिर रहा है...?

माही की गूँज, झाबुआ डेस्क।

संजय भट्टेवरा

लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए हैं और गाड़ी का सही संतुलन बना रहे जिसके लिए आवश्यक है कि, दोनों पहिए सही ढंग से काम करें। विरोध केवल मुद्दों पर आधारित होना चाहिए और मुख्य उद्देश्य देश हित ही होना चाहिए। व्यक्तिगत विरोध या व्यक्तिगत आरोप का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों ही पक्षों द्वारा इस राजनीतिक सूचिता का पालन नहीं किया जा रहा है न केवल विरोध के नाम पर व्यक्तिगत विरोध किया जा रहा है। बल्कि अशोभनीय भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। एक तरफ संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ ढाल बनाने से भी संकोच नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार का अनावश्यक बातों से न केवल देश का ध्यान भंग हो रहा है वरन् देश की असल समस्या से भी पक्ष-विपक्ष दूर होकर व्यक्तिगत आरोप में उलझ रहे हैं व



मूल मुद्दों से आमजन का ध्यान हटाया जा रहा है। पिछले दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार में निकाली जा रही यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में देश के प्रधानमंत्री की मां तो क्या किसी भी आम व्यक्ति की मां के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग निंदनीय है और इसकी कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा रतलाम में एक समाज के लिए कुछ टिप्पणी की गई

जिसको लेकर समाज के लोगों ने विरोध जताया, काले झंडे दिखाए यहा तक कि, उनकी गाड़ी के काँच भी फोड़ दिए गए।

निः संदेह स्वतंत्रता के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिला है। लेकिन इस अभिव्यक्ति की आजादी का यह आशय कहीं नहीं है कि, कोई भी कुछ भी कह दे। यही नहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा शराब को लेकर की गई टिप्पणी को भी भाजपा ने हाथों-हाथ मुद्दा बना लिया और प्रदेश भर में उनके पुतले जलाने लग गए। ऐसे में देश और प्रदेश का ध्यान इन तत्कालीन मुद्दों पर ही केंद्रित हो गया और असल मुद्दों से देश का ध्यान भटक गया।

पिछले कुछ वर्षों से यहीं चला आ रहा है पक्ष द्वारा किसी मुद्दों को विपक्ष द्वारा तो विपक्ष द्वारा दिए गए मुद्दों को सत्ता पक्ष द्वारा हाथों-हाथ लपक लिया जाता है और देश का पूरा ध्यान इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित हो जाता है। संसद का मानसून सत्र भी इस बार केवल हंगामे और तत्कालीन मुद्दों पर ही केंद्रित रहा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा केवल औपचारिक रूप से ही हो पाई। जबकि होना यह चाहिए की हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

शाह ने किया वीर जवानों का सम्मान, नक्सलवाद खत्म करने का दोहराया संकल्प

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में करेंगुडलु पहाड़ी पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नायक जवानों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।

शाह ने कहा कि, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करते, पकड़े नहीं जाते या समाप्त नहीं हो जाते, तब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी।

उन्होंने बताया कि, कठिन गमीं, ऊँचाई और हर कदम पर विस्फोटक के खतरे के बावजूद सुरक्षाबलों ने साहस और पराक्रम दिखाते हुए नक्सलियों का ठिकाना ध्वस्त किया। करेंगुडलु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के हथियार भंडार और सप्लाइ तंत्र को सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा बटालियन के जवानों ने नष्ट किया।

शाह ने कहा कि, नक्सलियों ने वर्षों तक देश के पिछड़े इलाकों को विकास से वंचित रखा, विद्यालय और अस्पताल बंद कराए तथा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुँचाने दिया। लेकिन अब सुरक्षाबलों के अभियान से पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक के क्षेत्र के करोड़ों लोगों के जीवन में नई आशा का संसार हुआ है।



गाजा पर इज़राइली हमला तेज़, बच्चों व पत्रकारों को भी नहीं बरखा

गाजा सिटी।

गाजा में मंगलवार को इज़राइल ने भीषण हमला किया, जिसमें कम से कम 105 फिलिस्तीनी मारे गए। मरने वालों में वे लोग भी शामिल हैं जो भोजन और पानी लेने के रास्ते में खड़े थे। अल-सबरा इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहाँ लगातार बमबारी से कई घर मलबे में तब्दील हो गए।

खान यूनिस् के पास अल-मवासी इलाके में पानी भरने पहुँचे 21 लोगों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें 7 मासूम बच्चे शामिल थे। घटनास्थल पर खून से सने पानी के डिब्बे और शव बिखरे मिले। गाजा प्रशासन ने आरोप लगाया कि अब आम नागरिकों को भी जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है।

किया जा रहा है।

एक अन्य हमले में अल-अफ परिवार का घर ध्वस्त हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर महिलाएँ और बच्चे थे।



वहीं, दो पत्रकारक़रस्मी सालेम और ईमान अल-जामलीक़की मौत से पत्रकारों की कुल संख्या 270 से अधिक हो गई है। यह युद्ध अब

पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक संघर्ष बन चुका है।

नाकाबंदी और हमलों के बीच लोग भूख से भी मर रहे हैं। केवल 24 घंटे में 13 लोगों की मौत भुखमरी से हुई है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 361 लोग भूख के शिकार हो चुके हैं।

इ. ज. र. 1 इली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि युद्ध निर्णायक चरण में है और सेना गाजा सिटी पर कब्ज़ा करने की तैयारी कर रही है। वहीं, बेरुजियम ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देकर अन्य देशों से भी ऐसा करने की अपील की है। गाजा प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से इसे नरसंहार और युद्ध अपराध घोषित करने की मांग की है।

मान्यता देकर अन्य देशों से भी ऐसा करने की अपील की है। गाजा प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से इसे नरसंहार और युद्ध अपराध घोषित करने की मांग की है।

भारत-जर्मनी ने मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमति

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके जर्मन समकक्ष योहान वेडफुल के बीच हुई वार्ता में व्यापार, तकनीकी सहयोग और सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊँचाई पर ले जाने का संकल्प लिया गया।

जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी 25 वर्ष पूरे कर चुकी है और दोनों देशों का वैज्ञानिक सहयोग भी पचास वर्षों से जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जर्मनी के समर्थन से यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द गति मिलेगी। जर्मन विदेश मंत्री ने भी भारत की आर्थिक और सामरिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि जर्मनी यूरोपीय संघ के भीतर भारत के पक्ष में मजबूत आवाज उठाएगा ताकि एफटीए को जल्द लागू किया जा सके। वेडफुल ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का उभरता केंद्र बताते हुए कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ साझेदारी से बड़े लाभ हासिल कर सकती हैं।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और नई तकनीक में सहयोग को भी विस्तार देने पर जोर दिया।



बाढ़ पीड़ितों के लिए कब आएगा राहत पैकेज-विपक्ष

नई दिल्ली। लगातार बारिश और बाढ़ से जूझ रहे राज्यों की स्थिति को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि प्रभावित राज्यों और खासकर किसानों के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए।

राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में हालात बेहद गंभीर हैं। हजारों परिवार घर और जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र की सक्रिय मदद जरूरी है। उन्होंने आग्रह किया कि राहत एवं बचाव कार्यों की गति भी और तेज की जाए।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों के लिए लाल अलर्ट जारी किया है। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में सबसे ज्यादा 203 मिमी वर्षा दर्ज हुई है, जबकि जम्मू, रामन, बनिहाल और अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश हुई।

जेल से बाहर आया मुंबई का डॉन

मुंबई।

माया नगरी मुंबई का गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली 17 वर्ष बाद जेल से बाहर आ गए। गवली 2007 से हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी, जिसके बाद बुधवार को वह जेल से बाहर निकले।

76 वर्षीय अरुण गवली पर शिवसेना के नगरसेवक कमलाकर जमसांडेकर की हत्या का आरोप था। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गवली पिछले 17 वर्षों से जेल में थे और उनकी अपील अदालत में लंबित है।

मोडिया रिपोर्टों के अनुसार नागपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोपहर को रिहा किया। इस दौरान परिवार और समर्थकों ने उनका स्वागत किया।

अरुण गवली को ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा दी थी। 9 दिसम्बर 2019 को गवली ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने गवली की जमानत पर मुहर लगाई।

गौरतलब है कि अरुण गवली 2004 से 2009 तक महाराष्ट्र की चिंचपोकली विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2012 में महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 17 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया था।



कांग्रेस प्रवक्ता पर दोहरी वोटर आईडी का आरोप, आयोग ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपना नाम दर्ज करवाया है, यानी उनके पास दो वोटर पहचान पत्र मौजूद हैं। इस मामले पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।



दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पवन खेड़ा को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण कराने के मामले में अपना पक्ष रखना होगा। इसके लिए उन्हें 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि यह कार्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए उन्हें कारण बताना होगा कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि पवन खेड़ा ने जंगपुरा (पूर्वी दिल्ली) और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र दू दोनों में वोटर पहचान पत्र बनवा रखा है। मालवीय ने कहा कि यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि इससे दोहरे मतदान की आशंका भी पैदा होती है। उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस «वोट चोर» पार्टी है।

भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें भी यह जानकारी अमित मालवीय की पोस्ट से ही मिली। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2016-17 में ही उन्होंने एक मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक वह नाम नहीं हटाया। खेड़ा ने कहा, यदि नाम अभी तक नहीं हटा तो इसमें मेरी गलती नहीं बल्कि चुनाव आयोग की लापरवाही है।

भारत के तीन दिवसीय दौरे पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री

नई दिल्ली।

अमेरिकी शुल्क की वजह से दुनिया में बनी अस्थिरता के बीच सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेस वांग भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। पत्नी के साथ उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुवार (4 सितंबर) को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें आपसी सहयोग, आर्थिक साझेदारी को मजबूती देने और साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श होगा।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में वांग का यह पहला भारत दौरा है। उनके साथ उनकी पत्नी, सिंगापुर की मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा वांग की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होगी।

पिछले साल सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की यात्रा की थी, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक जा पहुंचे थे। इस यात्रा में भारत और सिंगापुर के बीच पांच समझौतों पर



हस्ताक्षर होंगे, जिनका संबंध नागरिक उड्डयन और अंतरिक्ष से है। इसके साथ ही यह दौरा दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी को नए आर्थिक अवसरों तक ले जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर भारत की

«पूर्व की ओर देखो» नीति का अहम भागीदार है।

प्रधानमंत्री वांग 4 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्चुअल माध्यम से महाराष्ट्र में कटेनर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। सिंगापुर के बंदरगाह प्राधिकरण ने

इस परियोजना में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। संभावना है कि दोनों नेता बैठक के दौरान बंदरगाह परियोजना को समर्पित करेंगे। सिंगापुर भारत में निवेश का एक बड़ा स्रोत है। वर्ष 2014 से अब तक यह 175 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें कोरोना काल के बाद करीब 60 अरब डॉलर का निवेश हुआ।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दौरान दोनों पक्ष साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। सूत्रों के अनुसार दोनों देश पानी के अंदर मौजूद केबल के जरिए भारत से सिंगापुर तक सौर ऊर्जा निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे, जिसका इस्तेमाल डाटा कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा।

भूटान के प्रधानमंत्री शेर्पा टोबगे भी बुधवार से भारत की चार दिवसीय (3 से 6 सितंबर तक) यात्रा पर आए हैं। वह गया, अयोध्या और नई दिल्ली जाएंगे। 5 सितंबर को प्रधानमंत्री टोबगे से राजधानी के आईटीसी मीयां होटल में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शिष्टाचार भेंट करेंगे।

जर्जर मार्ग से आवागमन करने वाले ग्रामीणों में भारी नाराजगी



माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्मित सारंगी हाईवे से चौपाटी तक मार्ग की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि, अब लोगों का पैदल चलना भी दुश्चर हो रहा है। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि, जब तक सड़क का नया निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो जाता तब तक कम से कम इस मार्ग के गड्ढे ही भरवा दीजिए ताकि इस

मार्ग पर सुचारू रूप से एक आवागमन हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि, सारंगी बस स्टैंड से चौपाटी के बीच सड़क जर्जर होकर सैकड़ों जगह से टूट गई है। सड़क में अनेकों स्थान पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। जिनमें बरसात का पानी भर गया है। बरसात के समय पैदल चलने वाले राहगीरों को, टूट-झीलर, फोर झीलर गाड़ी वालों को परेशान होना पड़ता है।

इधर विभाग का कहना है कि, इस रोड के टेंडर लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

टेंडर ओपन होते ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

बताते कि, यह मार्ग गुजरात को महाकालेश्वर उज्जैन एवं तारखेड़ी धाम जाने के लिए प्रमुख मार्ग है। इस सड़क पर लोग उप तहसील कार्यालय तथा सारंगी का प्रमुख बाजार होने से अपने रोजमर्रा के कामों से आते-जाते हैं। इसके अलावा कृषक वर्ग भी खाद बीज एवं कृषि संबंधित कार्यों के लिए रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। स्कूल के बच्चे भी इसी रोड से आना जाना करते हैं जिन्हें कठिनाइयों का

सामना करते हुए यात्रा पूर्ण करनी पड़ती है।

ग्रामीणों ने बताया कि, अभी और भी बारिश होना बाकी है। उससे पहले इस मार्ग पर गड्ढे भर कर व्यवस्थित की जाए, ताकि आने-जाने वालों को समस्या न हो।

गौरतलब है कि, रायपुरिया, बरवेट, सारंगी, करवड़ 24 कीलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए 52 करोड़ रु स्वीकृत हुए हैं। जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। टेंडर ओपन होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

मुकेश लोहार ने बताया कि, बस स्टैंड से चौपाटी तक मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़क की खस्ताहाल होने पर विभाग का उदासीन रवैया बना हुआ है जिससे आमजन परेशान है।

व्यापारी अनिल बंबोरी ने कहा कि, सारंगी बस स्टैंड से चौपाटी तक मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिसमें पानी भरा रहता है। जहां वाहन सवार अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं, सड़क जब बनेगी तब बनेगी फिलहाल गड्ढे भरवाए जाए।

एसडीएम और तहसीलदार ने झूलो का स्वागत कर की पूजा

माही की गूंज, पेटलावद।

वर्षों से चली आ रही देव झूलनी ग्यारस पर नगर के मंदिरों से निकलने वाली झाकियों का स्वागत तहसील



परिसर में आईएसएस एसडीएम तनुश्री मीना व प्रभारी तहसीलदार अनिल बघेल द्वारा झूलो का स्वागत और पूजा अर्चना की गई। बरसते पानी में एसडीएम मीना ने झूलो की पूजा अर्चना की। उक्त परंपरा वर्षों से चली आ रही है। नगर के कई मंदिरों से भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और नगर भ्रमण कर तहसील परिसर में पहुंचते हैं। जहां तहसील के मुखिया द्वारा स्वागत किया जाता है। बारिश के बावजूद झूलो का उत्साह कम नहीं था झूलो के साथ भीगते हुए छोटे-छोटे बच्चे अखाड़े में करतब दिखा कर साथ में चल रहे थे। स्वागत के दौरान एसडीएम, तहसीलदार सहित तहसील स्टाफ उपस्थित रहा।

ढोल ग्यारस: बरसते पानी में थिरकते भक्त

माही की गूंज, भागल।

ढोल ग्यारस बड़ी ही उत्साह से मनाया गया। ग्राम में ही भगवान की पालकी श्री राम मन्दिर से निकाल कर



खवासा रोड पुल पर आई। उसके पश्चात वहां किसी ने भुट्टे तो किसी ने ककड़ी भगवान को भेंट करी। धार्मिक गंगा में ग्रामीण बरसते पानी में खुब झूमेते नाते नजर आए। बताया जाता है, ढोल ग्यारस पर्व भगवान श्री ऋषि के जन्म के बाद सवा महीना होने के बाद उनकी माता उनके अंतर वस्त्र धोने के लिए जलाशय की पूजा करने के लिए जाती है। इसी उपलक्ष्य में मन्दिर से भगवान की सवारी निकाली जाती है। जिसे ढोल धमाकों के साथ जलाशय पर पहुंची। उसके पश्चात आरती उतारी गई तथा फिर प्रसाद वितरण की गई। वही रात्रि में भजन किर्तन का आयोजन भी रखा जाएगा।

डायलिसिस की सुविधा नहीं होने से मरीज हो रहे परेशान जरूरी मापदंड पूरे करने के बाद सिविल हॉस्पिटल को नहीं मिली मशीन

माही की गूंज, पेटलावद।

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों को सुविधा देने के नाम पर सरकार ने केवल बड़े-बड़े भवन बना दिए हैं और सुविधा के नाम पर व्यवस्था आज भी शून्य है। यहां के पेटलावद सिविल हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी से ग्रस्त डायलिसिस के मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है। परेशान मरीजों को झालुआ और रतलाम जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लम्बे समय से पेटलावद सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन की सुविधा शुरू करने की बात कही जा रही थी लेकिन अब तक मशीन नहीं लग पाई है। जबकि सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीन लगाने हेतु सारे मापदंड पूरे होने के बाद मशीन नहीं आने के कारण लोगों को अन्य जगहों पर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है।

मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी एमएल चौपड़ा ने बताया कि, डायलिसिस की सुविधा के लिए जो मशीन लगनी है, इंजीनियर द्वारा दिए गए सभी मापदंड पूरे कर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख कर जानकारी दे दी गई है।

झकनावदा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौर ने बताया कि, मंत्री निर्मला भूरिया से मशीन के लिए मांग की जाएगी।

उर्वरक वितरण व्यवस्था की हो सघन मॉनीटरिंग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य हो

माही की गूंज, झालुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि, जिलों में उर्वरक वितरण के संबंध में जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्था बनाए। उपलब्ध उर्वरक की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहे। उर्वरक वितरण की व्यवस्था में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। जिलों में यदि उर्वरक वितरण को लेकर अव्यवस्था होती है तो उसके लिए जिला कलेक्टर उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण की स्थिति की बुधवार को

मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, जिलों में उर्वरक उपलब्धता की सघन समीक्षा की जाए। साथ ही जिले में उपलब्ध उर्वरक के स्टॉक की जानकारी जनप्रतिनिधियों से भी साझा करें। इससे किसानों को जिले में उर्वरक उपलब्धता की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन डबल लॉक, पैक्स और निजी विक्रय केंद्रों का आकस्मिक सत्यापन और उनकी मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करें। अतिरिक्त विक्रय केन्द्र की आवश्यकता होने पर उनका संचालन तत्काल आरंभ किया जाए। कृषि, सहकारी बैंक, विपणन संघ के अधिकारी निरंतर सम्पर्क में रहें।

डॉ. यादव ने उर्वरक वितरण व्यवस्था के संबंध में प्रदेश के जिले के कलेक्टरों से चर्चा की। कलेक्टर

द्वारा बताया कि, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सतत् सम्पर्क और संवाद सुनिश्चित करते हुए वितरण व्यवस्था में उनका सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही टोकन वितरण और उर्वरक वितरण को अलग-अलग किया गया है। टोकन तहसील कार्यालय से बांटे जा रहे हैं और वितरण विक्रय केन्द्रों से किया जा रहा है। किसानों के लिए टोकन वितरण की व्यवस्था फोन कॉल द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। उर्वरक वितरण केन्द्रों पर डिस्पले बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड पर टोकन नंबर प्रदर्शित कर उर्वरक वितरण किया जा रहा है। डिस्पले बोर्ड पर जिले में उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा भी प्रदर्शित की जा रही है।

अतिवृष्टि की स्थिति में सजग और सक्रिय रहे

प्रशासन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, प्रदेश में जिन-जिन क्षेत्रों में भी अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को क्षति हुई है, वहां राहत के लिए तत्काल कार्रवाई आरंभ की जाए। साथ ही जनहानि और पशु हानि की स्थिति में 24 घंटे में राहत उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ के दौरान अस्थायी कैम्प व्यवस्था, राशन वितरण, भोजन वितरण आदि की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामग्री सभी संभावित स्थानों पर उपलब्ध हो। आगामी दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना है। सभी जिलों में पुलिस प्रशासन सक्रिय और सजग रहते हुए पुल-पुलिया में बैरिकेटिंग और बाढ़ की स्थिति में पुल क्रास न करने की चेतावनी की व्यवस्था जैसी सभी आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करें।

मूक बधिर बच्चों के साथ मनाया गणेश चतुर्थी का त्यौहार

माही की गूंज, झालुआ।

कलेक्टर नेहा मीना द्वारा डीडीआरसी प्रांगण में स्थित चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स के हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया गया।

कलेक्टर द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हॉस्टल में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मूर्ति स्थापना के दौरान पूजा और आरती में सम्मिलित हुई। गणेश चतुर्थी के प्रति बच्चों में उत्साह देखते ही बनता है। उन्होंने प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना कर गणपति स्थापना की। मूकबधिर छात्रों ने कलेक्टर का सांकेतिक भाषा में अभिनंदन किया। इस पर कलेक्टर द्वारा भी सांकेतिक भाषा में उनका अभिवादन स्वीकार किया। बच्चों द्वारा बनाये गये मिट्टी की गणेश जी की सराहना की गई।

कलेक्टर द्वारा बच्चों के साथ भोजन की गुणवत्ता का भी जाँच की गई। कलेक्टर द्वारा लाइट नहीं होने पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए इनवर्टर की बैटरी लगाने के निर्देश दिए।



अंचल में धूमधाम से मनाया गया तेजा दशमी पर्व



माही की गूंज, खवासा।

त्याग, बलिदान और वचन बढ़ता की प्रतिमूर्ति लोक देवता तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली तेजा दशमी अंचल में धूमधाम के साथ मनाई गई। एक दिन पूर्व अंचल के सभी तेजाजी मंदिर पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। तथा जागरण का आयोजन किया गया। वहीं कई स्थानों पर तेजाजी की कथा का नाट्य मंचन भी किया। उल्लेखनीय है कि, लोक देवता तेजाजी की अंचल में बहुत अधिक मान्यता है और कई गांवों में तेजाजी नाटक मंडली बनी हुई है। रात्रि जागरण के पश्चात सुबह ब्रैडबाजो के साथ शोभायात्रा निकाली गई। जो गांव में भ्रमण के पश्चात तेजाजी मंदिर पहुंची जहां आरती उतारने के पश्चात मंत्र धारियों की मंत्र उतारने तथा ताती (धागा) तोड़ने का सिलसिला चला जो शाम तक जारी रहा। इस दिन अधिकांश व्यक्तियों द्वारा व्रत

रखा जाता है और तेजाजी के मंदिर पर नारियल, अगरबत्ती चढ़कर एक समय भोजन किया जाता है।

एक दिन का मेला लगाया गया

कुछ वर्षों पूर्व तक खवासा में तेजादशमी से क्षेत्र में सुप्रसिद्ध महावीर मावेशी मेले की शुरुआत हो जाती थी। लेकिन कुछ वर्षों से पंचायत द्वारा मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। लेकिन तेजा दशमी के अवसर पर लगने वाला एक दिवसीय मेला उस प्राचीन मेले की याद अवश्य दिलाता है। बच्चे उत्साह के साथ मेले में शामिल हुए। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी।

माही की गूंज, भागल।

लोक देवता सत्यवीर तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस पर तेजा दशमी का पर्व बड़ी

धूमधाम से मंगलवार को मनाया गया। जिसमें बड़ी संख्या में सत्यवीर तेजाजी महाराज मंदिर पर भक्त पहुंचे तो वहीं नवमी की रात को सत्यवीर तेजाजी महाराज की कथा का रसपान भी भक्तों ने करा। मंगलवार को मंदिर पर हवन पूजन के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। गांव में दो जगह से तेजा दशमी का जुलूस निकाला जिसमें मादलदा रोड व भामल बाजना मुख्य मार्ग पर दोनों मंदिर पर तेजा दशमी का जुलूस बड़े उत्साह के साथ निकाला गया। वहीं पूजा अर्चना के बाद निशान को पुनः मंदिर पर ले जाया गया। मंदिर परिसर में मंत्र धारी ने बड़ी श्रद्धा से निशान चढ़ाए गए। साथ ही संप्रदेश से पीड़ित की ताती भी मंदिर परिसर में काटी गई।



तेजा दशमी पर्व पर सुख समृद्धि की कामना

माही की गूंज, सारंगी।

भादवा माह की शुक्ल पक्ष दशमी पर श्री सत्यवीर तेजाजी महाराज की जयंती मनाई गई। नगर के पाटीदार मोहल्ले में स्थित सत्यवीर तेजाजी महाराज के मंदिर पर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रही। एक दिन पहले नवमी के दिन रात में श्री सत्यवीर तेजाजी महाराज की कथा का आयोजन रखा गया जिसमें पंडित अविनाश उपाध्याय द्वारा तेजाजी महाराज की कथा सुनाई। तेजा दशमी के दिन ग्रामीण क्षेत्र में भी तेजाजी मंदिर पर कार्यक्रम आयोजित हुए, ढोल नगाड़ों के साथ निशान लेकर नगर भ्रमणकर तेजाजी मंदिर पहुंचे। वहां पर मंत्र



व्यवस्थाओं पर कटाक्षः

अवैध आहतों को सरकार लघु उद्योगों में शामिल कर पैदा करे रोजगार के अवसर

कुफुरमुत्ते की तरह बढ़ रही अवैध आहतों की संख्या, ढाबों की आड़ में परोसी जा रही शराब

माही की गूंज, झाबुआ ।

कहने को तो सरकार ने शराब के आहतों को बंद कर दिया है और बड़े शहरों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बात की जाए शहरों से लगी हुई शराब की दुकानों और ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहा सरकार की ये रोक न पहले थी न ही आहते बंद करने के निर्णय के बाद कोई फर्क पड़ा है। अवैध आहतों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई स्थानों पर ये आहते ढाबों की आड़ में तो कई जगहों पर केवल शराब परोसने के लिए स्थान बना दिए गए हैं। इतना ही नहीं शराब ठेकेदार तक नियम के विरुद्ध शराब की दुकान के

आस चढ़र शेड या हरी मेट के कमरे बना कर खुले आम सुरा प्रेमियों के बैठने की व्यवस्था कर रहा है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और लाइसेंसी शराब की दुकानों के पास में ये व्यवस्था खुले आम देखी जा सकती है।

ढाबों की आड़ में चल रहे आहतों को लघु उद्योग में शामिल करे सरकार...?

अवैध आहतों और ढाबों पर बिकने वाली शराब को लेकर कितने ही समाचार प्रकाशित किए जा चुके हैं जो आबकारी और पुलिस के लिए उगाही का एक और

अस्त्र बन कर अवैध शराब विक्रेताओं से वसूली का माध्यम कार्रवाई के नाम पर डरा के बना दिया जाता है। लगातार मुद्दा उठाने के बाद भी कोई बड़ी नियमित कार्रवाई देखने में नहीं आती। ऐसे में सरकार को इन अवैध आहतों को जो की ढाबों की आड़ में खुलेआम चल रहे है उन्हे लघु उद्योग में शामिल कर सक्सी के साथ नए व्यवसाय के रूप में विकसित करना चाहिए...! लाईसेंसी शराब ठेकेदार के क्षेत्र में पड़ने वाले इन अवैध आहतों को ठेकेदार के माध्यम से सरकारी मदद से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लघु उद्योगों सहित अन्य मदो से रोजगार के लिए दिए जाने वाले लोन का सरकारी

आम जनता के लिए सुव्यवस्था के साथ बैठने योग्य बनाना चाहिए। ताकि ग्रामीण, शहरी क्षेत्र सहित मुख्य मार्गों से निकलने वाले वाहनों से आने-जाने वाले को विशेष सुविधा मिल सके। इस तरह शराब ठेकेदार के माध्यम से

टारगेट भी पूरा हो जाएगा। वही इस प्रकार की व्यवसाय के लिए युवा भी आगे आयेगें।

खाद्य विभाग भी नहीं देखता, अपडेट हो जाए तो खाद्य विभाग करे कार्रवाई

खाद्य विभाग लगातार क्षेत्र भर में किराने की दुकानों, रेस्टोरेंट और बड़ी होटलों पर सर्चिंग कर जांच करते रहते हैं। लेकिन अवैध ढाबों पर आबकारी व पुलिस के साथ-साथ खाद्य विभाग की टीम भी नहीं फटकती। जबकि इन ढाबों में ज्यादातर ढाबों पर खुले आम घंटिया

सामग्री का उपयोग होता है और गंदगी की भरमार होती है। बात करें जिला मुख्यालय जिले की तो यहा बिना गिनती के ढाबे सहित ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र में इन अवैध आहतों की बाढ़ सी आई हुई है यहा तक की चौराहो, स्कूल, कालेज व मंदिरों के आस-पास भी कई स्थानों पर शराब के अवैध अड्डे व ढाबे-आहते देखे जा सकते हैं। ऐसे में सरकार, शराब ठेकेदार के माध्यम से इन अवैध ढाबे- आहते व शराब के अवैध अड्डो को लोन व सक्सीडी देकर वैध करवा दिया जाए और सुरक्षा और साफ-सफाई के मापदंड तय कर दिए जाए तो खाद्य विभाग द्वारा भी समय-समय पर इनकी जांच की जाए।

कलेक्टर का निरीक्षण व्यवस्थाओं पर मरहम

माही की गूंज, कुंदनपुर। कृष्णपाल सिंह ठाकुर

अपने प्रशासनिक अमले के साथ झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने क्षेत्र के कालापान व गवसर उप स्वास्थ्य केंद्र व आंगनवाड़ी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर का अपने अमले के साथ इस तरह से आकस्मिक निरीक्षण किया जाना सराहनीय कार्य कहा जा रहा है। परंतु क्या इस तरह के निरीक्षण के साथ स्थाई रूप से अनियमितताओं को खत्म किया जाएगा, के भी सवाल सामने आते हैं।

मंगलवार को क्षेत्र के कालापान व गवसर में उप स्वास्थ्य केंद्र व आंगनवाड़ी पर निरीक्षण किया और अनियमितताओं को तरासने का कार्य कलेक्टर ने किया। कालापान में सामने आया कि, यहां पर करीब 58 महिलाएं गर्भवती हैं इसमें से 18 गर्भवती महिलाएं मजदूरी के लिये पलायन पर हैं।

कलेक्टर को मिली उक्त जानकारी के साथ यह सामने आता है कि, जिस गर्भवती महिला को डॉक्टर, प्रसव होने तक भारी वजन नहीं तोकने की सलाह देते हैं, और उन्हें आराम करने को कहा जाता है। ऐसे में इस गर्भवती अवस्था में एक ही उप स्वास्थ्य केंद्र के अधीन 18 गर्भवती महिलाएं अपने परिवार के पालन-पोषण के लिये पलायन पर जाकर भारी-भरकम सामान तोक महिलाएं मजदूरी कर रही हैं। ऐसे में राणापुर ब्लॉक या जिले में उसी हजारों गर्भवती महिलाएं अपने परिवार के पालन-पोषण के लिये बाहर पलायन कर मजदूरी कर रही है, यह तय है ऐसे में यह विषय बड़ा चिंतन का भी है।

वही गवसर में माती फलिया व नाती फलिया में लगने वाली आंगनवाड़ी कई दिनों से नहीं खुल रही है। वही कालापान के आंगनवाड़ी केंद्र चंगोड फलिया में कई

गड़बड़ियां मिली। वही कलेक्टर ने सभी गर्भवती महिलाओं से अनुरोध किया कि, प्रसव की तारीख आने पर तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा का उपयोग करें। किसी भी असुविधा या समस्या की स्थिति में नजदीकी आशा, एएनएम, सीएचओ से संपर्क करें व सुरक्षित प्रसव के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाएं। आंगनवाड़ी बंद मिलने के संबंध में संबंधित जानकारी को चेक करने के निर्देश दिये। यूवीन पर प्रत्येक बच्चे की एंटी किये जाने व कोई बच्चा टीकाकरण से ना छूटे के निर्देश दिये। वही चंगोड की आंगनवाड़ी केंद्र पर मिली गड़बड़ी पर कार्यकर्ता के वेतन काटने के निर्देश दिये।

बिज्र पर खुले में हुआ प्रसव पर कोई जांच व चर्चा नहीं

बता दे कि, गत शनिवार रात्रि में गवसर निवासी मुकेश मचार की 24 वर्षीय पत्नी सकीना मचार गर्भवती होकर अपने मायके ग्राम लम्बेला में थी। रात्रि में सकीना को प्रसव पीड़ा होने पर 108 एंबुलेंस पर संपर्क किया लेकिन एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हुई थी। जिस पर पैदल ही किसी वाहन की व्यवस्था नहीं होने पर प्रसव हेतु उप स्वास्थ्य केंद्र कुंदनपुर लाया जा रहा था कि, उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले ही भमची नदी के ब्रिज पर प्रसव पीड़ा बढ़ी। जिसपर साथ में आ रही परिवार की महिलाओं ने अपनी सूझबूझ के साथ उसी ब्रिज पर गर्भवती सकीना को लेटा दिया और खुले में छत्ते की आड़कर प्रसव करवाया और एक बच्चे ने जन्म लिया। इसी बीच कुंदनपुर के कुछ रहवासी सूचना मिलते ही ब्रिज पर पहुंचे और एएनएम क्रिस्टीना गणावा को फोन किया। एएनएम बिना वक्त गवाए भमची नदी के ब्रिज पर पहुंची और बच्चे की नाल काटी गई।

उक्त दो दिन पूर्व खुले में हुए उक्त प्रसव के संबंध में कलेक्टर ने न ही कोई चर्चा की और न ही कोई जांच की कि, 108 एंबुलेंस प्रसव के पूर्व युक्त महिला को क्यों उपलब्ध नहीं हो पाई थी। ऐसे में कलेक्टर के इस तरह के निरीक्षण सराहनीय जरूर है लेकिन अनियमितताओं पर महज मलहम लगाने का कार्य ही कहा जा सकता है। क्योंकि ग्रामीण दूर अंचल में आज भी प्रसव के दौरान एंबुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। गवसर की तरह कई ऐसी आंगनवाड़ी है जो नहीं खुल रही है। स्कूलों पर शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। जहां पहुंच रहे हैं वहां पर शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व शिक्षा पर गहन चिंतन कर एक ऐसी स्थाई व

निष्पक्ष टीम बनाकर नियमित व सख्त कार्रवाई के साथ इन अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। न की निरीक्षण कर वाहवाही व कार्रवाई के नाम पर लिपा-पोती कर अनियमितताओं के इस दिमक को स्थाई रूप से दुर नहीं किया जा सकता।



— गवसर व कालापान में कलेक्टर का आकस्मिक निरीक्षण।

हलचलः अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ऑफलाईन यानि संकुल प्रिंसीपल, वीडिओ की बल्ले-बल्ले

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले भर में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की चर्चा जोरों पर है। जनजातीय कार्य विभाग में ऑफलाइन प्रति वर्ष जुलाई बित जाने पर स्कूल की सुध लेने वाला जवाबदेही व जिम्मेदारी निभाने वाले आनन फानन में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर शोषणिक स्थिति में सुधार का दावा करते हैं। पर अंदर खाने पर ऑनलाइन की बजाय विभाग ऑफलाइन में कुछ जनप्रतिनिधि बिचोलिए व अतिथि शिक्षक नियुक्ति व संकुल प्रिंसीपल अंधा बाटे रैवड़ी अपने अपने को दे या ले दें कर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं बगैर बिज्ञाति।

जिले में कलेक्टर नेहा मीना की आंखों में धूल झोंकते मेघनगर ब्लाक में ऐसी नियुक्ति हुई कि, कुछ संकुल में जहां योग्यता को धता बता संख्या बल बताकर मनमानी के साथ कुछ लोगों की नियुक्ति हुई। मेघनगर संकुल में एक संस्था में विज्ञान के मिडील स्कूल में दो शिक्षक तों गुजरात सीमा के संकुल में सामाजिक कार्य विभाग से बीएसडब्ल्यू की योग्यता वाले को वर्ग दो को वर्षों से रखा जा रहा है। जबकि उक्त पद मिडिल स्कूल में नहीं है। वही गत वर्ष बीएड नियमित करने वाले भी अतिथि शिक्षकों ने शासन की आंखों में धूल झौख जिन्हें छातृवृति भी मिली व स्कूल से मानदेय भी लेने का प्रयास किया। वही जिन्होंने संस्कृत विषय व हिन्दी नहीं पढ़ा बीए में वह हाईस्कूल में संस्कृत पढा रहे हैं। बीएससी वाले बगैर बीए में अंग्रेजी साहित्य में पढ़े अतिथि शिक्षक अंग्रेजी पढाने हेतु पदस्थ किए गए। बीई की योग्यता इंजिनियर क्षेत्र में है पर बीएससी पात्र गणित की जगह उन्हें नियुक्त कर दिया जो शाला में शिक्षकों के परजनों को कही पुत्रवधू कही पत्नी कही भाई-बहन। विधायक वीरसिंह भुरिया के क्षेत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के नाम से अवैध उगाही तो कम्प्यूटर शिक्षक के नाम भी प्राचार्य के परिवार के लोगों की जनचर्चा जोरो पर है।? वही मिडील स्कूल, हायर सेकंडरी में बगैर डीएड, बीएड के फार्म आखिर संकुल प्राचार्य द्वारा कैसे स्वीकृत किए जा रहे है जो भी जांच का विषय है। ?सांदिपनी स्कूल मेघनगर भी अतिथि शिक्षकों का गड़ बन रहा है। थांदला, पेटलावद, रानापुर आदि स्थानों पर योग्यता पूर्ण पदस्थ शिक्षकों को प्राथमिकता न देते हुए नये लोगों की नियुक्ति जांच का विषय है। आखिर नवागत सहायक आयुक्त इस मुद्दे पर कब गंभीर होगी या बीईओ व प्राचार्य द्वारा नियुक्ति को लेकर क्लीन चिट की चर्चा जोरों पर है।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने उत्तारी आरती

माही की गूंज,पेटलावद।

पुराना नाका के मित्र मंडल द्वारा गणेशोत्सव हर्षोउल्लास से मनाया जा रहा है। नगर के विभिन्न स्थानों पर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं विराजित कर आमजन धर्म लाभ ले रहे हैं। पुराने नाके के भगवान गणेश जी की आकर्षित प्रतिमा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गणेश उत्सव समितियों द्वारा विभिन्न धार्मिक संगठनों और वरिष्ठजनों से बप्पा की आरती उतारने का लाभ भी दिया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड पर पुराना नाका मित्र मंडल की और से गणेशोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। पांडाल को आकर्षक विद्युत साज-सज्जा कर सजाया गया है। इसके अलावा प्रतिदिन मुख्य यजमानों को आमंत्रित कर आरती का लाभ दिया जा रहा है। सोमवार को महाआरती का लाभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकमल मालू डामोर के साथ विजेंद्र जादौन और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा लिया गया। इस अवसर पर नगर के कांग्रेसी कार्यकर्ता नारायण सिंह गहलोत, गोल्ड हामड, जीवन सिंह ठाकुर, विक्रम चावड़ा, रघुनंदन सतीगीया, बबलू राठौड, कचरू आजना, गौरव जानी के साथ बड़ी संख्या में बप्पा के भक्तगण उपस्थित थे। महाआरती के बाद यहां महिलाएं, पुरुष, बच्चे की एक लाइन लगवाकर उन्हें सल्पाहार महाआरती के यजमान द्वारा वितरित किए। इस आयोजन में महिलाएं, बच्चों और युवा वर्ग के लड़कों द्वारा गरबा रास खेलने का भी आयोजन पुराना नाका के मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। जिसका भरपूर आनंद नगर के भक्त ले रहे हैं।

दुर्घटनाओं के कारण बनते सड़कों में गड़ढे और नियमों की अनदेखी कर चलते ओव्हर लोड

माही की गूंज, झाबुआ।

सड़क दुर्घटना इन शब्दों को सुनते ही मन में अनेक दुःखःद आशंकाएं पनपने लगती हैं। फिर जब जनहानि नहीं होने की बात पता चलती है तब मन से आधा भय समाप्त होता है किंतु उस दुर्घटना में अन्य सामग्री की हानि से परिवार और समाज की क्षति पहुंचती है वह भी दुःखदायी होती है।

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना ने मन मथिष्क तक को दुःखःद कर झकझोर दिया। 30 सितंबर को रात रेत से भरा ओव्हरलोड डम्पर छोटा उदयपुर से निकला जिसके बाद इंदौर अहमदाबाद मार्ग को छोड़कर वह ग्रामीण रास्ते पर चला गया, जो कि जंगल से होकर गुजरता है, अतः निस्देह उस रास्ते के बारे में उसे पहले से ही बता दिया गया होगा या उसे पता होगा। रेत से भरे इस वाहन ने नींद में सो रहे एक मासूम के साथ उसके माता-पिता को भी काल का ग्रास बना डाला। वाहन की गति इतनी तेज थी कि वह संभल भी नहीं सका और सड़क के पास बने घर में जा चुसा।

पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि वाहन किसका था, उसका ड्राइवर कौन था। जानकारी के लिए जब कालिदेवी टीआई से चर्चा की गई तब थाना प्रभारी ने बताया कि अभी कार्यवाही जारी है ड्राइवर फरार है, वाहन के कागज अभी उनके पास नहीं हैं, न ही उनके पास रॉयल्टी है। वाहन नंबर के आधार से जिसके पास गए थे उसके

मोह में जाने-अंजाने दुर्घटनाओं में मृत हुए लोगों की मौतों के मुख्य जिम्मेदार हैं। फिर जब तक ये सरकारी लोग नियमों को उल्लंघन करते रहेंगे तब तक प्रत्येक वाहन चालक नियमों की अनदेखी करता रहेगा और कभी न कभी हादसों को अंजाम देगा।

पुलिस, आरटीओ, या खनिज, या वन, या फिर आबकारी ये विभाग खानापुर्ति करने के लिए चेकींग चलाते हैं जब इनकी डायरी रिकार्ड अनुरूप भर जाती है तब इनकी

कार्यवाही रुक जाती है। फिर जब कोई हादसा होता है तब कलेक्टर की आंख खुलती है और फिर तेजी से कार्यवाही ने निर्देश जारी होते हैं।

झाबुआ जिले में वर्तमान में ऐसे तीन हादसे हैं जिसने मासूमों के जीवन को पलक झपकते ही मृत कर दिया। सजेली पुलिस थाना पर

कार्यवाही रुक जाती है। फिर जब कोई हादसा होता है तब कलेक्टर की आंख खुलती है और फिर तेजी से कार्यवाही ने निर्देश जारी होते हैं।

झाबुआ जिले में वर्तमान में ऐसे तीन हादसे हैं जिसने मासूमों के जीवन को पलक झपकते ही मृत कर दिया। सजेली पुलिस थाना पर

सकरी नोकरशाहों के लिए, जो अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से कुछ नियमों को कुछ दिनों तक लागू करते हैं और फिर भुल जाते हैं, तब समस्या यथावत रहती है। सरकार का बुद्धिजीवी वर्ग इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है।

वाहनों की गति पर नियंत्रण नहीं है, ओव्हरलोड प्रत्येक वाहन में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसके कारण सड़के खराब होती हैं। सड़कों में गड़्डे भी दुर्घटना का कारण हैं।

हालांकि नियमों को नए प्रकार से बनाने की आवश्यकता है, पहले से नियम तो बने हुए हैं परंतु उन नियमों का पालन करने वाले कोई भी नहीं है और न ही उन नियमों को सख्ती से पालन करवाने के लिए जिम्मेदार

लोग सामने आते हैं। किसी भी जिले में जब कोई नया अधिकारी जाता है तब वह शुरुआत में सख्त रैखा अपनाता है फिर जैसे ही लालच, भ्रष्टाचारियों, से भेंट हो जाती है तब फिर से कार्य शैली में नर्माहट आ जाती है।

बहरहाल, सोए हुए शेरा के मुंह में हिरण नहीं आता, उसे जाग्रत होना पड़ता है। समाज में भी जागृति के लिए शिक्षा का अनुरोध लेकर उन नियमों को प्रसारित करना चाहिए। कड़े कानून और सजा के साथ-साथ ड्राइवर के समुह बनाकर उनकी दो दिवसीय या तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित करवानी चाहिए। यातायात और परिवहन के नियम को लिपि बद्ध कर कहानी, कविता, निबंध के माध्यम से पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित करना चाहिए जिससे बच्चों में यातायात के प्रति शुरू से ही सम्मान रहे और नियमों का पालन करने की बुद्धि में सक्रीयता बनी रहे।

अतः सभी सरकारी अधिकारी और सरकार को इस समस्या के समाधान का उचित परिणाम सामने लाना होगा, अन्यथा हादसों और इन हादसों में मरने वालों की प्रतिवर्षानुसार संख्या बढ़ती जाएगी जो की देश के लिए एक आपदा का रूप ले सकती है।



रिश्का बेरागी



संपादकीय

उत्तमीदों की चिप



भारत ने टेक क्रांति की तरफ बढ़ते हुए पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित कर लिया है। इसरो की सेमीकंडक्टर लैब इस कामयाबी की साक्षी बनी है। पहली मेड इन इंडिया चिप का उत्पादन गुजरात के साणंद स्थित पायलट प्लांट से शुरू होगा। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 18 अरब डॉलर से ज्यादा के कुल निवेश वाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देश में चल रही हैं। जिनमें से एक पंजाब के मोहाली में स्थित है। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले चिप क्षेत्र में भारत की यह दस्तक उत्साह जगाने वाली है। भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिये उत्सुक है। तभी सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। हालांकि, इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है। फिलहाल आधुनिक समय की इस जादुई चिप के उत्पादन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। यहां तक कि छोटा-सा देश ताइवान दुनिया के लगभग साठ फीसदी से ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर रहा है। जिसमें करीब नब्बे फीसदी उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल हैं। दरअसल, कोविड संकट के बाद आधुनिक तकनीक व उन्नत उपकरणों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर होड़ पैदा हो गई है। निस्संदेह, भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में एक दिग्गज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान-विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने में भारत के लिये मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारत में चिप उत्पादन परियोजनाओं में जापानी निवेश बढ़ रहा है।

निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान-विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिये दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे हम वैश्विक दबाव से मुक्त होकर अपनी आपूर्ति शृंखला को मजबूत बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की दिशा में भारत का एक सशक्त पक्ष यह भी है कि दुनिया के लगभग बीस फीसदी चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी क्षेत्र में कामयाबी के लिये भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार बड़ी घरेलू कंपनियों को संबल देने के लिये डिजाइन लिंकड इंस्टिट्यूट यानी डीएलआई के तहत दिए जा रहे लाभ के विस्तार के साथ ही, इसके तहत दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिसके तहत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओं के लिये केंद्र व राज्यों से प्रोत्साहन के रूप में परियोजना की कुल लागत का सत्तर फीसदी मिलना जारी रह सकता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पचास फीसदी पूंजीगत सहायता दे रही है। वहीं राज्य सरकारें कुल परियोजना लागत का बीस फीसदी प्रोत्साहन दे रही हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में गेम चेंजर टेक क्रांति माना जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा भी कि सरकार इस मिशन और उसको तैयार करने से जुड़ी डीएलआई योजना के अगले फेज पर काम कर रही है। निश्चित रूप से केंद्र के प्रयासों से भारत चिप उत्पादन के वैश्विक महत्वाकांक्षी अभियान की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकता है। दरअसल, डिजिटल डिवाइसों का मस्तिष्क कहा जाने वाला सेमीकंडक्टर कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, कार, सैटलाइट जैसे उन्नत डिजिटल डिवाइस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपकरणों की कार्यकुशलता उन्नत चिप की ताकत पर निर्भर करती है। साधारण शब्दों में कहे चिप पतली सिलिकॉन वेफर पर बने लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टर्स का संजाल है। जो कंप्यूट करने, मेमोरी प्रबंधन व सिग्नल प्रोसेस करके डिवाइस को उन्नत बनाती है। उम्मीद है कि भारत का स्वदेशी चिप इस साल के आखिर तक बाजार में आ सकेगी। जिसका असर जियोपॉलिटिक्स पर तो होगा ही, नये रोजगार सृजन का वातावरण भी बनेगा।

वर्दी में फौजी से लेकर युनिफॉर्म बनने तक

भारत की अधिकांश नीतिगत शब्दावली अभी भी सैनिकों की पेंशन को एक 'बोझ' के रूप में वर्णित करती है। जबकि यह एक गुलतफहमी है। जिसे दायित्व कहा जाता रहा है, वह दरअसल एक विलंबित मान्यता है। जिसे लागत कहकर खारिज किया जाता है, वह असल में गणतंत्र के लिए द्वितीय लाभांश है। कुरुक्षेत्र से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, निष्ठा भारत में निरंतर क्रम है, और यह 40 साल उम्र में खत्म नहीं हो जाती।

ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा प्रमाण है- 22 मिनट की सटीकता, 88 घंटे की सतर्कता, और फिर युद्धबंदी। आज की बिखरी विश्व व्यवस्था में बहुत कम राष्ट्र अपने पास इतने बड़े पैमाने का अनुशासन होने का दावा कर सकते हैं। निष्ठा कोई नई नहीं है। इसने 1971 में टैंकों को मेघना नदी पार करवा दी, 2025 में इसी ने दृष्टि की सीमा से परे ठिकानों पर सटीक आयुधों की मार का प्रदर्शन किया। निष्ठा भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक विरासत है।

पेंशन के मायने ही गलत- ब्रिटिश हुकूमत ने पेंशन की रूपरेखा एक मान्यता के रूप में नहीं बनाई थी। एक ऐसा बंधन, जो वफादारी को बांधे रखने में पर्याप्त, लेकिन अपने हाल पर छोड़ देने में सदा नाकामी। आजाद भारत को यह रूपरेखा विरासत में मिली, और अर्धशास्त्रियों ने पेंशन को आर्थिक घाटा व निकासी मान, इस गलती को और पुष्टा किया।

लेकिन जिसे हमारे बहीखाते 'पेंशन बोझ' कहते हैं, वह वास्तव में नवीकरणीय पूंजी है- प्रति वर्ष 70,000 प्रशिक्षित सेवानिवृत्त फौजी, बिना किसी पुनः उपयोग योजना के, देश के अर्थतंत्र में शामिल होते हैं। उनपर लगे प्रत्येक रुपये में दशकों के कौशल, निर्णय शक्ति और सहनशीलता छिपी है, एक ऐसी पूंजी जिसे कोई अन्य राष्ट्र इतनी आसानी से व्यर्थ जाने देना नहीं चाहेगा।

हमारा अंध बिंदु - एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक के एक लेख में भानु प्रताप ने लिखा है- 'अग्रणी व्यवसायियों को अक्सर शिकायत रहती है कि देश में कुशल मानव पूंजी की कमी है, हालांकि इसका निर्माण करने को निवेश करने में वे सदा अतिचक्रु रहें।' इस बीच, हर साल हमारा गणतंत्र अपनी सबसे अनुशासित, मिशन को तैयार प्रतिभा को फालतू हुआ मानता आ रहा है, जबकि उन्हीं क्षेत्रों में कुशल कामगार लाने या पुनः प्रशिक्षण पर अरबों खर्च जाते हैं। यह

अकुशलता नहीं बल्कि औद्योगिक अनदेखी है। सही नीति से स्थिति सुधर सकती है। प्रतिबद्धता बनाम अनुबंध- भारत स्थायी भरोसे की अहमियत समझता है; यह स्मृति में अंकित है। फिर भी, नीतिगत शब्दावली में, उस भरोसे को का अर्थ अक्सर रोजगार से जोड़ दिया गया है। एक ऐसे लोकतंत्र में, जहां नौकरी ताकत पाने का शॉर्टकट हो, पेंशन को हक जताना मान लिया गया। बेहंगी योजनाएं नौकरी को अनुभव पाने का जरिया और प्रतिज्ञा को अनुबंध के रूप में देखने लगीं।

अल्प-सेवा योजनाओं का मोल- वे भर्ती को व्यापक बनाती हैं और युवा ऊर्जा

अनुभव से समझौता और मारे गये सैनिकों की जगह लेने के लिए नए युवा लाना। पश्चिम एशिया सशस्त्र लड़ाकू गुटों में बंटा हुआ है, जहां निष्ठा अर्जित नहीं, खरीदी जाती है। नतीजन, अंतहीन लड़ाइयां, बरसों खिंचने वाले युद्ध, जिनको केवल बही खातों और हताहतों के आंकड़ों से मापा जाता है। इसके अनुशासित लाभांश उपलब्ध हैं - बतौर अनाड़ी रंगरूत नहीं, न ही भाड़े के बंदूकधारी, बल्कि उच्च कौशल और निर्णय दक्षता प्राप्त स्त्री-पुरुष।

घर में व्यर्थ जाता लाभांश- हर साल हजारों सैनिक अपनी पेशेवर क्षमता के चरम

तक- गणतंत्र पहले से ही ऐसे सैन्य कौशल गढ़ता आया है जो किसी स्टार्टअप अर्थतंत्र में सबसे अधिक मांग वाली क्षमताओं को प्रतिबिंबित करते हैं: तनाव में भी सही निर्णय क्षमता, बड़े पैमाने पर रसद पहुंचाना, फ्रील्ड में तकनीक उपयोग, विपरीत परिस्थितियों में धीरज कायम रखना और अनिश्चितता भरे माहौल में दल की नेतृत्व क्षमता। ये कोई कपोल-कल्पित अवयव नहीं हैं; बल्कि युनिकॉर्न (बिलियन डॉलर की कंपनी) बनाने में जरूरी डीएनए हैं। एक द्वितीय-लाभांश नीति परस्पर जरूरतों का मिलान कर करके, सेवानिवृत्त दिग्गजों को उन नियोक्ताओं से जोड़ सकती है, जो इन्हीं

म ी म ो (मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट) तकनीक का विकास किया, जो आधुनिक वायवरलेंस नेटवर्क उपकरण का आधार है। अरबों उपकरण उनकी इस खोज पर निर्भर हैं, जबकि भारत इसका बहुत कम लाभ उठा पाया।



जनरल एस.एस. मेहता



युद्ध का बदलता स्वरूप- अब युद्धक क्षमता का मूल्यांकन केवल संख्याबल और मारक क्षमता से नहीं मापा जाता। विदेशों में, सर्वोत्तम हार्डवेयर उपयोग हेतु तैनात हैं, फिर भी यूक्रेन युद्ध बिना किसी समाधान अपने चौथे वर्ष में भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने कुछ अलग देखा यानी किफायती आयातित एवं स्मार्ट स्वदेशी आयुध एवं उपकरण, जो अनुभवी और गहन प्रशिक्षित सज्जानात्मक 'स्कैनवेयर' द्वारा संचालित हैं। युद्ध विराम से पहले 22 मिनट और 88 घंटे तक टकराव चला, उसके बाद संयम बरतने वाली शानदार राजनीतिक रणनीति। यह किसी दुश्मन के लिए अनुशासन-चालित, असहनीय सम्मिश्रण होता है।

ईश्वरीय कृपा और धुरी- विदेशों में जिन संघर्षों को हम आज देखते हैं, वे एक अगिन परीक्षाएं हैं, उनके लिए महंगी, किंतु हमारे लिए शिक्षाप्रद। यह अनुबंध की सीमाओं को उजागर करता है, और हमें याद दिलाता है कि क्या ज्यादा देर तक टिकाऊ है। सबक स्पष्ट है कि भारत का द्वितीय लाभांश घर बैठे इंतजार कर रहा है, वहीं पहनकर सेवा करने और युनिकॉर्न कंपनी बनाने की संभावना लिए।

निवारण का हमारा नुस्खा- किफायती और स्मार्ट (एआई युक्त) युद्धक सामग्री। द्वितीय लाभांश से निर्मित युनिकॉर्न कंपनियों का साथ। निष्ठा जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होती। रीड के रूप में देशभर में फैली हमारी विरासत एक ताकत है। यह 1971 में कारगर रही व 2025 में भी काम कर गई स्टार्टअप अर्थतंत्र की नींव बना दिया। भारत के पास इसका अपना प्रमाण है। नौसेना अधिकारी आरोग्यस्वामी पॉलराज ने सोनार सिस्टम पर काम करते वक्त के अनुभव से

पर सेवानिवृत्त श्रेणी में शामिल हो जाते हैं - अगुवाई करने की दक्षता प्राप्त इंजीनियर, आपूर्ति शृंखला में पारंगत, चिकित्सक, संचार विशेषज्ञ आदि। गणतंत्र इस पूंजी को आकार देने में दशकों लगा देता है, लेकिन फिर इनके पुनः उपयोग की कोई योजना न बनाकर, इसको व्यर्थ जाने देता है। फौज में आपूर्ति शृंखला में काम चुका एक पूर्व सैनिक इस क्षेत्र में कमियां दूर कर सकता है। फ्रील्ड अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सिंग सहायक गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को विस्तार दे सकती है। उन्नत प्रणालियों में कुशलता अर्जित कर चुके एक तकनीशियन को सेवानिवृत्त उपरांत अक्सर बैंक गार्ड लगाकर उसका सारा अनुभव बेकार जाने दिया जाता है। फौजियों से बनी प्रादेशिक सेवा को भी पुनर्कल्पित कर चुके एक तकनीशियन को व्यास कमियों को पाटा जा सकता है। ये पुनर्निवेश की बाट जोहते लाभांश हैं।

सेवा कौशल से युनिकॉर्न कंपनी बनने

क्षमताओं को ढूंढ़ रहे हैं, मसलन, साइबर, एआई, स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति शृंखला, स्वच्छ ऊर्जा आदि क्षेत्र में। भारत जिन्हें अब स्वयं जाने दे रहा, वह अरबों डॉलर के उद्यमों की आकली लहर के लिए कच्चा माल है। वैश्विक प्रमाण- पश्चिमी सेवानिवृत्त फौजी साइबर सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला और एआई क्षेत्र में युनिकॉर्न कंपनियां खड़ी कर चुके हैं, जिन्होंने रणभूमि में समस्या आने पर त्वरित सही निर्णय लेने में अर्जित अपने अनुभवों को अरबों डॉलर कमाने में बदल दिया। दक्षिण कोरिया में, अनिवार्य सेना सेवा ने जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और गेमिंग उद्योग में अग्रणी लोगों को जन्म दिया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। इसाइल ने सेवानिवृत्त फौजियों को अपने स्टार्टअप अर्थतंत्र की नींव बना दिया। भारत के पास इसका अपना प्रमाण है। नौसेना अधिकारी आरोग्यस्वामी पॉलराज ने सोनार सिस्टम पर काम करते वक्त के अनुभव से

हिमालयी परिस्थितिकी के अनुकूल बने विकास योजनाएं

बीते पांच अगस्त को हरसिल और गंगोत्री के बीच खीरगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से अचानक आई तेज बाढ़ और भारी मलबे ने धराली में तबाही मचाई। इस आपदा ने दर्जनों मकान, होटल और दुकानें नष्ट कर दीं, कई लोग मृत और अनगिनत लोग लापता हो गए। हरसिल में भी बाढ़ के कारण ग्यारह जवान लापता हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी द्वारा बचाव कार्य जारी है। शीतकालीन पर्यटन से जुड़े इस क्षेत्र का मार्ग बाधित हो गया है। पारंपरिक नदी मार्गों में पथर, मिट्टी और मलबे के अवरोध से बाढ़ का प्रवाह दिशा बदल गया, जिससे त्रासदी और भी गंभीर हुई।

उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच स्थित धराली क्षेत्र उत्तरकाशी के पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र में आता है। हाल ही में यमुनोत्री मार्ग पर रयाना चट्टी में बादल फटने से गंभीर हादसा भी हुआ। ऐसे नाजुक और सामरिक क्षेत्रों में खनन, सड़क निर्माण, जलाशय और सुरंग निर्माण तथा औद्योगिकीकरण के कार्यों में सरकारों और जनता को आत्म-नियंत्रण बरतना चाहिए। पर्यावरण हितैषी तकनीकें अपनानी जरूरी हैं। उत्तरकाशी जिले में लगातार विभिन्न आपदाओं का सामना करना पड़ता रहा है जैसे सिलव्यारा सुरंग दुर्घटना व भयावह उत्तरकाशी भूकंप। मनेरी भाली परियोजना के पास झीले बनती रही और भटवाड़ी के धंसने की घटनाएं भी नहीं नहीं। भटवाड़ी ब्लॉक में ही धराली आता है।

गोमुख से लेकर उत्तरकाशी मुख्यालय और चिन्याली सीढ़ तक का क्षेत्र बीते दो दशकों से लगातार आपदाओं से ग्रस्त है। यहां गंभीर भूस्खलन, बाढ़ें और तबाही बार-बार होती रही हैं। खासकर उत्तरकाशी में वरुणावर्त पहाड़ अपने भूस्खलनों से 2003 से लोगों को भयभीत कर रहा है। क्षेत्र के पहाड़ 1990 के तीव्र भूकंप से पहले से ही कमजोर हैं, जबकि 4-4.5 तीव्रता के भूकंप नियमित आते रहते हैं। इस दौरान उत्तरकाशी और आसपास के पुल टूटते रहे हैं, जिससे कई गांव कई दिन तक अलग-थलग पड़ जाते हैं। वर्ष 2010 से इस पूरे क्षेत्र में लगातार बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो रही हैं। चट्टानें गिरने से जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है, गांव ध्वस्त हो रहे

हैं और उन्हें पुनः बसाने की आवश्यकता सामान्य सी बात हो गई है। गंगोत्री और गोमुख का संकट व्यापक रूप से ज्ञात है, जबकि भटवाड़ी और अस्सी गंगा के क्षेत्र भी ऐसे ही संवेदनशील हैं, जहां पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। निस्संदेह, यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से नाजुक है। 2017 में उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में पंद्रह गांवों की प्रतिनिधि महिलाएं इसी इकोसेंसिटिव क्षेत्र में काटे जाने के लिए चिन्हित पेड़ बचाने के लिए संकल्पबद्ध हुई थीं। इस क्षेत्र में 1990 में हुए भयावह विनाश के बाद 2016 में इसकी आधारशिला रखी। बिना पर्यावरण प्रभाव आकलन के इस सड़क पर काम शुरू किया गया था। तब एनजीटी में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय में भी मामला पहुंचा था। स्मरण रहे कि चारधाम राजमार्ग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हैदर आल खान के चेयरमैन ने पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को 13 अगस्त 2020 को एक पत्र लिखा था कि इस परियोजना में वन्यजीव व वानिकी के नियमों की बेहद गंभीर अवहेलना व उल्लंघन हुआ है। इन कृत्यों ने



कहा गया था कि अब सारे मकान, भवन आदि भूकंप-रोधी बनाए जाएंगे। सुरंगें नहीं बनाई जाएंगी। किन्तु आज भी आप सरकारी स्तर पर भूकंप-रोधी निर्माण या नदी तटों के समीप बसावटों को रोकने में गंभीरता शायद ही पाएंगे।

महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना उत्तरकाशी इकोसेंसिटिव क्षेत्र से ही बनती है। प्रधानमंत्री ने साल

2020 में प्रधानमंत्री को लिखा था कि उत्तराखंड में बारहवासी चारधाम मार्ग के निर्माण के दौरान गंगा हिमालयी बेसिन को गंभीर पर्यावरणीय हानि हो रही है। उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण के भी संकेत दिए थे। आज की



वीरेंद्र कुमार

इन दुर्भाग्यपूर्ण आपदाओं को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। इस यथार्थ को अतिशिष्ट स्वीकार कर लिया जाना चाहिये कि गोमुख से उत्तरकाशी तक इकोसेंसिटिव क्षेत्र के नियमों का पालन करना ही होगा और पर्यावरण समत विकास की दिशा में ही आगे बढ़ना होगा। भारत सरकार का दिसंबर 2012 का भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील अधिसूचना के गजट में भी कहा गया था कि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार दो साल के भीतर जनता से विशेष रूप से महिलाओं के परामर्श से आंचलिक महायोजना बनाएगी, और इसका अनुमोदन पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्र सरकार से कराएगी। किन्तु 2014 तक जोनल प्लान बनाने के लिए उसने महिलाओं या आमजन को साथ नहीं लिया।

हर बार धराली जैसी आपदाओं के बाद संपादकीयों में में उत्तराखंड के संदर्भ में यह जरूर कहा जाता है कि राज्य में अनियोजित विकास, बेतहाशा पेड़ कटान व जनसंख्या दबावों से ये आपदाएं आ रही हैं, परंतु शायद ही मीडिया सरकारों को इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में संतुलन बनाने के दावों को लेकर चुनौती देता है। जो स्थानीय जन

सालाना 6 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग ले रहे राशन

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में सरकारी राशन योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जाती है ताकि आर्थिक तंगी से जुझ रहे लोगों को 2 वक्त का भोजन मिल सके। जिले में 2300 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है।

फिर भी वे सस्ते गेहूँ-चावल के लिए सरकारी दुकानों की लाइन में खड़े नजर आते हैं। सवाल यह है कि जब आमदनी अच्छी है तो गरीबों का हक मारने की क्या मजबूरी है? खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया है और 14 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके नाम राशन पोर्टल से हटा दिए जाएंगे और उन्हें भविष्य में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में सरकारी राशन लेने वाले 2 लाख 40 हजार परिवार हैं। जिनके कुल सदस्य 9 लाख 65 हजार हैं। अधिकारियों का कहना है कि पात्रता नियमों के अनुसार अब तक सभी को राशन मिल रहा है। उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी होने के बाद पहली बार वार्षिक आय 6 लाख से अधिक होने को लेकर उपभोक्ताओं से जवाब मांगा जा रहा है।

जिले में सरकार की तरफ से 2300 लोगों की सूची पोर्टल पर जारी हुई, जो अभी योजना का लाभ उठा रहे



हैं। नोटिस संबंधी कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब सरकार छंटनी के मूड में है। नोटिस के जवाब से असंतुष्टि के बाद उनका राशन बंद कर दिया जाए या फिर उनसे रिकवरी भी हो सकती है। जैसे अन्य शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों से होती है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन परिवारों के पास अच्छी आय है, वे बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। जब वे सरकारी राशन उठा लेते हैं तो पात्र लोगों को

अपने हक से वंचित होना पड़ता है।

आयकर विभाग की सूची से खुला राज

आयकर विभाग से मिली जानकारी के आधार पर प्रदेश सरकार ने ऐसे हजारों राशन कार्डधारियों को लिस्ट खाद्य विभाग के पोर्टल पर डाली है। जिनकी सालाना आय 6 लाख से 10 लाख या उससे अधिक है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने बताया कि हमने

2300 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सभी को अपने-अपने ब्लॉक के एसडीएम कार्यालय में नोटिस का जवाब प्रस्तुत करना होगा।

मशीन का डाटा अपडेट नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रहे राशन

बारिश को देखते हुए सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया था। अब सितंबर शुरू हो गया है लेकिन राशन केंद्रों पर ताले लगे हैं। इस संबंध में जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी मशीन का डाटा अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण राशन नहीं दे रहे हैं। उपभोक्ताओं को राशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है

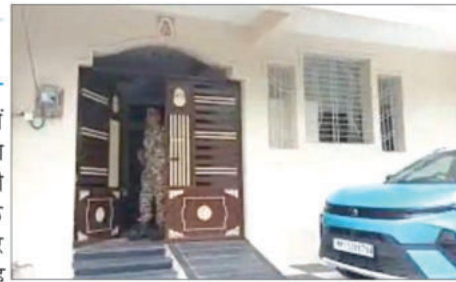
57 हजार से ज्यादा का सत्यापन बाकी

जिले में 9.65 लाख हितग्राही सदस्य हैं, जिनमें से 9.07 लाख (94 प्रतिशत) की ई-केवाईसी हो चुकी है। जबकि 57 हजार से अधिक का सत्यापन बाकी है। विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही शासन स्तर से सीधे राशन का आवंटन जारी हो रहा है। जिनका सत्यापन शेष है, उनके कार्ड सक्रिय नहीं किए जाएंगे।

जिला आबकारी अधिकारी के घर ईडी का छापा

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में जिला आबकारी अधिकारी के घर बुधवार अल सुबह



प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सुबह 4 बजे जिले के यश नगर स्थित मकान पर दबिशा दी।

आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत के बाद की जा रही इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी का आठ दिन पहले ही मंदसौर से दतिया तबादला हुआ है, हालांकि वे अभी रिलीव नहीं हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह मंदसौर स्थित आबकारी अधिकारी बीएल डांगी के घर पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और सुबह से ही अधिकारी के घर में छापेमारी को अंजाम दे रही है। जानकारी के मुताबिक, ईडी के छापे के समय पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के घर में कोई मौजूद नहीं था। इंदौर और भोपाल की 2 टीमों ने यहां दबिशा दी। घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।

दरअसल, बीएल डांगी मंदसौर

में नौकरी के दौरान काफी विवादों में रहे, उनके ऊपर पिपलिया मंडी शराब दुकान से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसके साथ ही मंदसौर शहर प्रतिबंध के बावजूद शहर से लगातार शराब बित्री की खबरें भी सामने आती रही ऐसे में उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठे। 22 अगस्त को उनका ट्रान्सफर दतिया हो गया था। आबकारी अधिकारी के घर छापेमारी से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा।

बीएल दांगी का हाल ही में मंदसौर जिला आबकारी पद से दतिया तबादला किया गया है, हालांकि, वह अब तक रिलीव नहीं हुए हैं। वहीं, दूसरी तरफ जांच टीम के सूत्रों का मानना है कि, इस छापामार कार्रवाई में बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में बीएल दांगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

3 बदमाशों ने नागदा की महिला को 40 घंटे खा डिजिटल अरेस्ट

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के नेहरू नगर और ग्राम गुणावद के तीन बदमाशों ने मिलकर नागदा क्षेत्र की 50 साल की महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। आरोपियों ने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बनकर महिला से 5 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए।

शिकायत पर बिरला ग्राम

थाना पुलिस ने सायबर सेल की तकनीकी सहायता से, मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से ढाई लाख रुपए और तीन मोबाइल जप्त किए। आरोपियों में एक युवती भी शामिल है।

बिरला ग्राम के वसंत विहार कॉलोनी निवासी सरोज माली (50) पति कुंदनलाल माली ने बिरला ग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया कि राजेश उर्फ राज ने अपनी महिला साथी व एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बनकर फोन लगाया और जेल में डालने व नागदा से उठाने की धमकी दी।



संबंधित होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। सायबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ राज (25), बलराम (32) पिता वरदीराम जाट दोनों निवासी ग्राम गुणावद और युक्ति

(25) प्रमोद बैरागी निवासी नेहरू नगर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ राजा से 1 लाख रुपए, बलराम के कब्जे से 89 हजार और आरोपी युक्ति से 1 लाख रुपए और तीन मोबाइल जप्त किए।

कार्रवाई में खाचरौद थाना प्रभारी धन सिंह नलवावा, बिरलाग्राम थाने के उपनिरीक्षक जितेंद्र पाटीदार, सायबर सेल के जे. प्रतीक यादव व टीम सहायक उपनिरीक्षक भूरिया मोहरे, गणेश पाल, गोपाल चावला, शर्मिष्ठा शूरला, हेमराज गुर्जर, संदीप यादव, चेतन जायसवाल, महेश परमाल की भूमिका रही।

महिला को 12 अगस्त की शाम 6 बजे आरोपियों ने फर्जी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बनकर 14 अगस्त तक 40 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने महिला को धमकाकर 5 लाख 9 हजार रुपए अवैध रूप से वसूल लिए। शिकायत पर ग्राम बिरला पुलिस ने आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने एक टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ा

घटना गंभीर प्रकृति व सायबर फ्रॉड से

अंग एवं देहदान जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

माही की गूंज, मंदसौर।

पी.एम. कॉलेज आफ एक्सर्सेस, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर (म.प्र.) के प्राचार्य प्रो. जे. एस. दुबे सर ने बताया कि मंगलवार को सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के द्वारा पी.एम. कॉलेज आफ एक्सर्सेस मंदसौर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, रेड रिबन

क्लब, यूथ रेडक्रॉस के संयुक्त तत्वावधान में अंग एवं देहदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सोमित्र सेठिया ने मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनके साथ सीनियर रेसीडेंट डॉ. अमृता भी कार्यक्रम में सम्मिलित रहें।

अपने संबोधन में डॉ. सोमित्र सेठिया ने अंग एवं देहदान की आवश्यकता, उचित समय और प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश

डाला। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का अंगदान लगभग आठ लोगों का जीवन बचा सकता है। विशेष रूप से नेत्र प्रत्यारोपण से अंधत्व से पीड़ित व्यक्तियों को पुनः दृष्टि प्राप्त हो सकती है। साथ ही, देहदान से चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानव शरीर रचना एवं रोग विज्ञान की गहन शिक्षा मिलती है, जो भविष्य की चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होती है। कार्यक्रम में चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर

के इंटर्नस द्वारा अंगदान के महत्व पर तैयार किया गया एक वीडियो भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं एवं संकाय सदस्यों ने अंगदान की प्रतिज्ञा लेकर समाजहित में इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान विभाग के डॉ. सन्तोष सिंह मालवीय, अशफाक हुसैन समेत एनएसएस स्वयंसेवक एवं राजनीति विज्ञान विभाग के विद्यार्थी उपस्थित रहें।

मेडीकल स्टोर का लायसेंस निरस्त

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले में दवाओं के विक्रय में सतत निगरानी एवं नशीली दवाओं के विक्रय के रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं सीएमएचओ डॉ. कमला आर्य के निर्देशन में विगत दिवसों में मेडीकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया।



खाद्य एवं औषधि प्रशासन औषधि निरीक्षक श्री प्रदीप अहिरवार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मैसर्स मण्डलॉई मेडीकल स्टोर्स तिलावद मैना तहसील कालापीलत का लायसेंस दवाओं के विक्रय बिल में अनियमितता एवं शेडयूल एच 1 दवा के विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर पांच दिवस के लिये निलंबित किया गया।

इसी तरह निरीक्षण के दौरान फर्म मैसर्स भारत मेडीकल स्टोर्स दुकान नंबर 1 मेन रोड, हनुमान मंदिर के सामने, बेरख, तहसील शाजापुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दवाओं के विक्रय बिल में अनियमितता, शेडयूल एच 1 दवा के विक्रय में अनियमितता, फिजिशियन सेम्पल पाये जाने, शीत संग्राहक औषधि के शीत संग्राहक तापमान पर नहीं पाये जाने एवं सक्षम व्यक्ति की अनुपस्थिति में दवाइयों का विक्रय किया गया। उपरोक्त प्रकरण में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंघन करने पर मेडीकल स्टोर का लायसेंस निरस्त किया गया।

चोरी के सामान के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, अकोदिया।

30-31 अगस्त की दरमियां रात को फरियादी अर्किट पिता सिद्धनाथ मेवाड़ा निवासी खेडीनगर की मोहम्मद खेड़ा स्थित डीजे की दुकान पर अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर दुकान के अंदर से 06 डीजे मोस्पेड एम्प्लीफायर मशीन, 1 मिक्सर मशीन एवं 1 डीबीएक्स मशीन चोरी कर ले जाई गई थी।

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अकोदिया में अपराध क्रमांक 213/2025, धारा 331(4), 305 बीएएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय एवं

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शुजालपुर निमेष देशमुख के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह राजपूत द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने लगातार अथक प्रयास, मुखबिर सूचना एवं साइबर सेल की मदद से आरोपियों को चिन्हित किया। तत्पश्चात कार्यवाही कर आरोपी अभिषेक पिता प्रेमनारायण चौधरी, उम्र 21 वर्ष, निवासी पोलायकला, विजयसिंह पिता केशरसिंह चांदना, उम्र 22 वर्ष, निवासी

पोलायकला, संतोष पिता आत्माराम सुर्यवंशी, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम बागोदा, चौकी तिलावद, विनोद पिता अनाखीलाल मेकचंद, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम बागोदा, दिलीप पिता मोतीलाल खेलवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी पोलायकला, विनोद पिता बाबूलाल सुर्यवंशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी रानीबडोद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों से 06 डीजे मोस्पेड एम्प्लीफायर मशीन, 01 मिक्सर मशीन, 01 डीबीएक्स मशीन (कुल कीमत लगभग 05 लाख रुपये), 02 मोटर साइकिल (कीमत लगभग 01 लाख 10 हजार रुपये) 'कुल रु 06 लाख 10 हजार रुपये' मश्रुका जप्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

फरियादी ने दिनांक 21 अगस्त को शुजालपुर सिटी में निकली महाकाल सवारी में आशु डीजे की प्रस्तुति दी थी। उसी दिन आरोपी दिलीप खेलवाल की नजर डीजे मशीनों पर पड़ी। करीब 10 दिन तक रेकी करने के बाद दिलीप ने अपने साथियों अभिषेक, विजय, संतोष, विनोद सुर्यवंशी एवं विनोद मेकचंद को शामिल कर चोरी की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया।

उक्त कार्य में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह



राजपूत, सर्जिन प्रदीप सिंह, प्रधान आरक्षक विपिन सिंह तोमर, सोनू जायसवाल, प्र.आर. ओमवीर सिंह जाट,

आरक्षक अभिषेक परमार, चालक शिवपाल, आर. अर्किट एवं साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संचालन दिलीप डांगी ने किया।

नृत्य नाटिका की भी हुई प्रस्तुति

साध्वी जी गीतार्थरेखाजी म.सा. के 500 आयम्बिल तप अनुमोदनार्थ सोमवार को लोढ़ुसाथ जैन धर्मशाला में दोपहर को नृत्य नाटिका गीता की भी प्रस्तुति हुई जिसमें संघ के महिला



मण्डल एवं बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी जिसे सभी ने सराहा तथा साध्वीजी के उत्कृष्ट तप साधना की अनुमोदना भी की।

दसलक्षण महापर्व पर हो रहे विभिन्न धार्मिक आयोजन

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में त्याग, तपस्या, संयम व साधना की आराधना के इस दसलक्षण पर्व पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिदिन श्रद्धालुजन मंदिर में विशेष धर्म आराधना कर रहे हैं।

मंदिर ट्रस्ट के संयोजक कोमल प्रकाश जैन पंछी व जितेन्द्र दोशी ने मंगलवार को बताया कि श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा व पूजा अर्चना विभिन्न पुण्यार्जक परिवारों द्वारा बिना किसी पंथ, ग्रंथ, एवं संत वद के, सामूहिक भक्ति संगीत के साथ सानंद संपन्न की जाती है।

मंदिर समिति के अध्यक्ष भरत कुमार कोठारी ने बताया कि इस आदर्श परम्परा का पालन करते हुए प्रातः 7 बजे श्री जी का अभिषेक व शांतिधारा एवं 8 बजे से नित्यरूप पूजन, पूजा पूजा, दस धर्म पूजन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आमंत्रित विद्वान विकास भैया शास्त्री के सानिध्य में भक्ति संगीत के साथ संपन्न हो रही है, दोपहर में 3 बजे तत्पार्थ सूत्र का वाचन एवं सामूहिक प्रतिक्रमण व संस्था 7 बजे से श्री जी की 48 दीपों से महामंगल आरती मनोज जैन, कपिल जैन तरुण, प्राची जैन द्वारा भक्ति भजन व संगीत से हो रही है। रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक दस धर्म पर विशेष प्रवचन भी विकास भैया जैन शास्त्री



द्वारा किए जा रहे हैं पार्थ महिला मंडल द्वारा प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है

चल रहा तपस्या का दौर

मंदिर से जुड़े परिवारों में साधना बड़जात्या एवं अंगुरबाला गांधी द्वारा पंचमेरुजी के 5 उपवास किये गए एवं अनिल कुमार गांधी, पदमा पोरवाल, निकिता संदीप जैन के भी 10 उपवास की तपस्या चल रही है। पंचमेरु मंडल विधान किया गया। इस अवसर पर धर्मचंद्र बड़जात्या परिवार एवं पार्थ महिला मण्डल द्वारा मंदिर में दो रजत अभिषेक कलश हेतु राशि मंदिर समिति को भेंट की गई।

ताले खोलकर हुई 5 करोड़ की बैंक लूट, 12 घंटे में पुलिस का चौकाने वाला खुलासा

माही की गूंज, उज्जैन।

पुलिस ने मंगलवार के दिन जिले में हुई 5 करोड़ की बैंक लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के गिरफ्तार किया है। इस खुलासे के बाद नए जिहाद के बारे में पता चला है। इसमें से एक हिंदू युवक शामिल है। उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसके बाद चार अन्य मुस्लिम युवकों के साथ बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के खुलासे के साथ पुलिस अब पता लगा रही है कि कहीं इस हिंदू युवक का ब्रेनवाश तो नहीं किया गया। इसके बाद धर्म परिवर्तन कर सोची समझी रणनीति के तहत वारदात को अंजाम तो नहीं दिलाया गया।

दरअसल, उज्जैन पुलिस को बैंक चोरी की सनसनीखेज वारदात में बड़ी सफलता हाथ लगी। इसका खुलासा एसपी प्रदीप शर्मा ने मंगलवार की देर रात को किया। एसपी ने बताया कि सुबह करीब 10:00 बजे पुलिस को बैंक चोरी की जानकारी लगी। बताया गया कि महानंदा नगर स्थित एसबीआई की ब्रांच में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई। सूचना मिलते ही खुद एसपी प्रदीप शर्मा ने मोर्चा संभाला।

ताले तोड़कर नहीं खोलकर हुई चोरी

पुलिस को जानकारी दी गई कि रोज की तरह सुबह सफाईकर्मी और मैनेजर बैंक में पहुंचे। तब उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। वहीं, बैंक चोरी की सूचना पर एसपी, साइबर टीम, क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पुलिस को ख़ास बात पता चली। चोरी के दौरान बैंक के अंदर का कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं था। वहां के सभी ताले चाबियों से

खोले गए थे। इससे पुलिस को शंका हुई कि जरूर बैंक के अंदर का कोई व्यक्ति इस वारदात में शामिल है।

एफएसएल टीम ने फिंगरप्रिंट की जांच, साइबर टीम द्वारा वारदात के समय सक्रिय मोबाइल लोकेशन की जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई। जब पुलिस ने बैंक में ही काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्स कर्मचारी जय भावसार से पूछताछ की तो कई अहम खुलासे हुए। वारदात के कई सुरांग हाथ लगे।

बैंककर्मों ही निकला मास्टरमाइंड

जय भवसान ने अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनकर जीशान नाम रख लिया। साथ ही चार अन्य साथी साहिल, अब्दुल्ला, अरबाज और कोहिनूर के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। पांचों आरोपी रात करीब 2:30 बजे बैंक में घुसे। 35 मिनट के भीतर वारदात को अंजाम देकर 4 किलो 700 ग्राम सोना और 8 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। मास्टरमाइंड बैंक का आउटसोर्स कर्मचारी था। इसलिए उसके पास बैंक की चाबियां थीं।

पहले से की थी रेकी

पुलिस की गई शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि 15 दिन पहले 16 अगस्त को बैंक के ग्राउंडफ्लोर पर आग लगी थी। तब कर्मचारी जय भावसार अपने इन्हीं आरोपी दोस्तों को बैंक में सुधार कार्य करने लाया था। इन आरोपियों ने बैंक की पूरी तरह से रेकी की थी। वहीं, मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने जानबूझकर



गोल्ड लॉकर को खुला छोड़ा था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि बैंक में आग भी तो कहीं किसी योजना के तहत तो नहीं लगाई गई।

बैंककर्मचारियों पर गिरी गाज

चोरी की इस वारदात में बैंक के बड़े अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। बैंक में जय भावसार आउटसोर्स के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उसके पास बैंक की चाबियां होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक के आला अधिकारियों ने एसबीआई महानंदा नगर शाखा प्रबंधक पायल महेश्वरी, सेवा प्रबंधक सुरेन्द्र कुमार माधव, और केश अधिकारी अभिनव को तत्काल प्रभाव से निलंबित

कर दिया।

नेपाल भागने की थी तैयारी

12 घंटे के भीतर चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा करने वाली टीम को एडीजी ने 30 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नेपाल जाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। यदि समय रहते पुलिस ने इन्हें नहीं पकड़ती तो यह देश छोड़कर नेपाल चले जाते। इसके साथ ही पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि चोरी, डकैती जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए कहीं जिहादियों द्वारा यह नया सॉफ्ट तरीका तो नहीं खोजा गया है।

सिंधिया राजघराने की पगड़ी, चांदी की पालकी और गार्ड ऑफ ऑनर...

माही की गूंज, उज्जैन।

भाद्रपद की ढोल ग्यारस पर उज्जैन में भगवान कालभैरव की सवारी निकाली जाएगी। महाकाल



के सेनापति भैरव बाबा राजसी ठाट बाट के साथ निकलेंगे। शाम 4 बजे कलेक्टर और एसपी कालभैरव की पूजा-अर्चना कर पालकी को रवाना करेंगे। इसके बाद चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा की सवारी शुरू होगी। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।

उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध कालभैरव मंदिर स्थित है। मन्दिर में भगवान कालभैरव की चमत्कारिक प्रतिमा है। यह देश का एकलौता मंदिर है जहां प्रतिदिन मंदिरा का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह भैरव भगवान की प्रतिमा सीधे मंदिरा का सेवन भी करती है।

बाबा महाकाल के सेनापति की शाही सवारी

धर्म शास्त्रों के अनुसार कालभैरव भगवान शंकर के कोतवाल है। जहां भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है। वहीं, भगवान भैरव को क्षेत्रपाल (सेनापति) के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हल जानने के लिए सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उसी प्रकार भैरव भगवान भी क्षेत्रपाल की भूमिका निभाते हुए प्रजा की रक्षा के लिए वर्ष में दो बार नगर भ्रमण पर निकलते हैं।

सिंधिया घराने की पगड़ी से पूरा होता श्रृंगार

ढोल ग्यारस के दिन यहां विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के पहले भैरव बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। कालभैरव को सिंधिया राजघराने की पगड़ी पहनाई जाती है। यह विशेष तौर पर ग्वालियर से मंगवाई जाती है। यह पगड़ी मराठी शैली में होती है। दरअसल उज्जैन में सिंधिया राजघराने का शासन रहा है। इसलिए यहां महाकाल बाबा और कालभैरव के अलावा कई प्राचीन मंदिरों में सिंधिया राजघराने की परंपरा निभाई जाती है।

केन्द्रीय जेल में होती है पूजा

जिला कलेक्टर काल भैरव की पूजा करने के बाद ठाट बाट से शाही सवारी को रवाना करते हैं। सवारी के आगे पुलिस के घुड़सवार रहते हैं। उसके बाद हाथों में बंदूक लिए पुलिस की बटालियन चलती है। सवारी राजकीय ठाट बाट के साथ गाजे बाजे से निकालते हैं। सवारी मंदिर से होते हुए केन्द्रीय जेल तिराहा पर पहुंचती है। यहां जेल एसपी पालकी की पूजा करेंगे। वहीं, कैदी पुष्प वर्षा कर पालकी का स्वागत करेंगे। मान्यता है कि कैदी कालभैरव बाबा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और जेल से जल्दी छूटने की प्रार्थना करते हैं।

इन जगहों पर गुजरेगी सवारी

मंदिर के पुजारी पंडित ओमप्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि कालभैरव मंदिर से रवाना होकर नया बाजार, भैरवगढ़ नाका, माणकचौक, महेंद्र मार्ग होते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के सिद्धवट घाट पहुंचेंगी। यहां वैकुंठ द्वार पर भगवान कालभैरव और उनकी पादुकाओं का अभिषेक-पूजन होगा। जेल तिराहा से होते हुए वापसी होगी।

स्वच्छ हरित विद्यालय कार्यशाला का हुआ आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्वच्छ हरित विद्यालय से संबंधित कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया। इस अवसर पर डीपीसी कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि एवं सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के विद्यालय परिसरों को वातावरण के अनुकूल बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा बारिश के बाद दीवारों की रंगाई-पुताई कर परिसर को हरा-भरा बनाया जाए। इससे न केवल बच्चों को स्वच्छ एवं निर्मल वातावरण मिलेगा, बल्कि वे भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी प्रेरित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति को सुधारें और अनउपयोगी वस्तुओं को परिसर में इकट्ठा न होने दें। विद्यालय को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रेरणादायी वातावरण देने का सामूहिक प्रयास ही हरित क्रांति अभियान को सफल बनाएगा। इस दौरान उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी को इस अभियान के तहत जल, शौचालय, हाथ धोना, संचालन एवं रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ गतिविधियां आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

परथी दादा की पहचान से रोशन हुआ रिंगोल, विकास कार्यों को मिली गति

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर। फ़िरोज खान

देश में कई गांव ऐसे हैं जिनकी पहचान किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ी होती है और चंद्रशेखर आजाद नगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत रिंगोल की पहचान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परथी दादा है। उनकी विरासत सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इस गांव की पहचान है।

असाधारण जीवन और ईमानदारी की मिसाल परथी दादा का जन्म भले ही इसी क्षेत्र के ग्राम मालमसुरी में हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने गुजरात में नशामुक्ति और शराबबंदी के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। उनकी ईमानदारी और त्याग की भावना इतनी गहरी थी कि जब उन्हें दो राज्यों (गुजरात और मध्य प्रदेश) से स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन मिलने लगी, तो उन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश की पेंशन ली। उनका यह निर्णय आज भी लोगों को ईमानदारी की प्रेरणा देता है। ग्राम सरपंच महेश भुरिया ने परथी दादा की विरासत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से ही परथी दादा का की प्रतिमा बनाई गई, जो अब रिंगोल गांव



की पहचान बन गया है। यह प्रतिमा सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि गांव के लोगों की आस्था का केंद्र है। इसी प्रतिमा पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जैसे बड़े नेता आए और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिससे रिंगोल गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने जहां दो महत्वपूर्ण सड़कों को मंजूरी दी थी वहीं मुख्यमंत्री यादव ने गांव में दो नए सामुदायिक भवन और सात सड़कों के निर्माण की घोषणा की। ये सभी विकास

कार्य परथी दादा के नाम पर ही संभव हुए हैं। रिंगोल में हर साल 12 जून को परथी दादा के जन्मदिन पर युवा प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आईटीआई सेजावाड़ा व हायर सेकंडरी स्कूल बख्शर भी परथी दादा के नाम से ही संचालित होती है। पूर्व सांसद गुमानसिंह डामोर ने इस गांव को गौद भी लिया था। गांव में ज्यादातर किसान ही हैं, जो मक्का और उड़द की फसल लेकर जीवन यापन करते हैं। इतना ही नहीं गर्मी के मौसम में कुछ किसान सब्जियों की फसल भी लेते हैं।

गुंडों से हमले करवाकर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है भाजपा सरकार - कांग्रेस जिलाध्यक्ष

माही की गूंज, अलीराजपुर।

विगत दिनों रतलाम जिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए हमले के विरोधस्वरूप सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश पटेल के नेतृत्व मे सेकड़ो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाईक रैली निकालकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि अधिकारी संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्रसिंह बघेल को सोपकर गुंडा तत्वों के खिलाफ एफआईआर की माँग की।

घटना की घोर निंदा कर कार्रवाई की माँग की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए हमले के विरोध मे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय बोरखड़ पर जमा हुवे और यहां से पार्टी का झंडा लहराते हुए बाईक रैली निकाली। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुवे कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहाँ उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं ने गुंडों पर एफआईआर की माँग को लेकर ज्ञापन सोपा। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पटेल एवं पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर ने कहा की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा पूरे प्रदेश मे अवैध शराब, नशा कारोबार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। रतलाम में जीतू पटवारी के काफिले को जबरन रोकने और उनके वाहन को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है, जो कि लोकतंत्र गला

घोटने जैसा कृत्य है एवं उक्त कृत्य पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे हुआ है। उन्होंने कहा की सवाल यह है कि अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। संपूर्ण प्रदेश नशे के कारोबार, अवैध शराब और भ्रष्टाचार माफियाओ की सरपरस्ती में डूबी हुई है, भाजपा ने पूरे प्रदेश को उड़ता मग्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश की भाजपा सरकार जीतू पटवारी के अभियान से बोखला गई है और गुंडो का सहारा लेकर उन पर प्रयोजित हमले करवाकर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस इससे घबराने और डरने वाली नहीं है। जिला कांग्रेस उक्त घटना की घोर निंदा करते हुवे भाजपा के गुंडा तत्वों जो कृत्य में लिस थे उनके विरुद्ध न्याय न्यायिक कार्यवाही की माँग करती है।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भुवानसिंह बामनिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश पचाया, सुरसिंह सोलंकी, युवा विधानसभा कांग्रेस अध्यक्ष तरुण मंडलोई, वरिष्ठ नेता खुशींद अली दिवान, मुकेश गुप्ता, पार्षद दिलीप रावत, सरपंच संजय चौहान, प्रदीप रावत, खुमला भाई, जनपद सदस्य लालू भाई, जुनेद कुरैशी, राजू बामनिया, धनसिंह चौहान, कमल बघेल, सवलसिंह पचाया, राकेश चौहान, प्रकाश बेघेल आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।



1500वां जश्न ईद-ए-मीलादुन्नबी बच्चों के प्रोग्राम के साथ हुआ आगाज



माही की गूंज, अलीराजपुर।

ईद मिलादुन्नबी के मौके पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चार दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन जामा मस्जिद चोक पर बाद नमाज ईशा शुरू हुआ। जिसमें मदरसा नूर-ए-मोहम्मदी के बच्चों ने बद्-चद् कर हिस्सा लिया कुछ बच्चों ने शानदार तकरीरें पेश कीं, जिनमें उन्होंने सीरत-ए-नबी पर रोशनी डाली। वहीं, अन्य बच्चों ने नात खवानी कर महफिल को रूहानी बना दिया। हफ्द, नात-एक-नबी, तकरीर और

सवालोंने जवाब नात शरीफ पेश की। वहीं मदरसे के बच्चों के समूह ने मनकबत पेश किए। तकरीर की भी खूब सराहना हुई। आखिर में मुल्क में अमन-चैन और कोम की सलामती की दुआ के साथ देर रात प्रोग्राम संपन्न हुआ। आयोजन में बच्चों की वालदा, परिवार के सदस्य, रिश्तदार, मौजूद रहे। आयोजन में शहर काजी हाजी सैय्यद अफजल मियां, सैय्यद हनीफ मियां, सैय्यद असफाक मियां, पेश इमाम मुफ्ती अजमल रब्बानी, एव हाफिज सिराज साहब हाफिज अब्दुल रऊफ उपस्थित रहे।

आदि कर्मयोगी अभियान का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम हॉल में की गई। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने बताया कि यह अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो आदिवासी अंचलों की स्थानीय जरूरतों और समस्याओं पर केंद्रित रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर आगामी कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी रूप से कार्य किया जा सकेगा। अलीराजपुर जिले के 490 ग्रामों को 32 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है ताकि अभियान को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। कलेक्टर ने उपस्थित ब्लॉक ट्रेनरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और अभियान के सभी पहलुओं से रूबरू होकर इसे सफल बनाने में योगदान दें। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रखर सिंह, मास्टर ट्रेनर तथा जिले के 30 ब्लॉक ट्रेनर उपस्थित रहे।

देसी जुगाड़ से बना डाली पब्जी गेम वाली गाड़ी...

माही की गूंज, राजगढ़ (ब्यावरा)।

राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पुखराज सिंह ने देसी जुगाड़ से पब्जी गेम की बगी (छोटी गाड़ी) बनाकर सबको चौंका दिया। गेम से प्रेरित होकर उन्होंने इस अनोखी गाड़ी को कबाड़ से तैयार किया लोग इसे देखने आ रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं।



दरअसल, पुखराज सिंह को पब्जी गेम खेलने और उसमें बगी देखने का शौक था। उनके मन में विचार आया कि वे ऐसी ही बगी बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 3-5 महीने तक सामग्री जुटाई। पुखराज बताते हैं, "गाड़ी में पल्सर बाइक का इंजन, दो तरह के वाहनों के पहिए, बाइक और कार के शॉकअप लगाए गए हैं। वहीं, राजधानी भोपाल के एक मैकेनिक के सहयोग से यह सपना पूरा हुआ। बगी अब तैयार है, सिर्फ डेंटिंग-पेंटिंग और लाइट्स लगाने का काम बाकी है।" पुखराज के अनुसार, इसे बनाने में 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। उनके मित्र सनी ने बताया कि पुखराज इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं। सनी के मुताबिक, पुखराज ने मैकेनिक से चर्चा कर भोपाल के कबाड़खाने से बाइक और कार के पहिए, शॉकअप और पल्सर बाइक का इंजन जुटाकर बगी तैयार की। अब इसमें पेंटिंग के बाद लाइट भी लगाई जाएगी। फिर यह बगी लोगों के लिए अजुबा होगी। बहरहाल, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का युवा पुखराज का यह जुनून और जुगाड़ हिंदुस्तान में कुछ नया करने वालों की मिसाल है।

मौत के बाद मुर्दों को नहीं मिलता न्याय, अंतिम संस्कार के लिए परेशान होते ग्रामीण

मंत्री निर्मला भूरिया के क्षेत्र की स्थिति दयनीय, राजनैतिक भविष्य पर लग सकता है ग्रहण

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

तस्वीर आपको अंदर तक झकझोर देगी क्योंकि यहां मुर्दे भी चीख-चीख कर व्यवस्था से न्याय मांगते नजर आयेगें। बात पेटलावद विकास खंड की है जहां से जनता द्वारा चुनी विधायक निर्मला भूरिया वर्तमान में सरकार में कैबिनेट मंत्री है। लेकिन उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में भारी लापरवाही सामने आ रही है। कहीं घंटिया पुल निर्माण तो कहीं कन्यादान राशि के भुगतान के लिए परेशान हितग्राही तो कई जगह अंतिम संस्कार तक के लिए संघर्ष करते ग्रामीण देखे जा सकते हैं। कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही और मंत्री जी की खुद के क्षेत्र की अनदेखी सामने आ रही है जिससे उनके भविष्य की राजनीति पर भारी ग्रहण लगाता दिख रहा है। फिलहाल बारिश चल रही है और पेटलावद विकासखंड में अंतिम संस्कार से जुड़ी बड़ी परेशानियां उजागर हुई हैं। बारिश के अलावा अन्य दिनों में अंतिम संस्कार के लिए लोग संघर्ष करते नजर आते हैं। लेकिन बारिश के दौरान ये संघर्ष ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे दो वीडियो वायरल हुए जिनको देखने के बाद मुर्दा व्यक्ति भी खून के आशु लेकर दुनिया से विदा हो रहा है।

प्लास्टिक की पन्नी लगा कर अंतिम संस्कार करने को मजबूर ग्रामीण

विकास खंड पेटलावद की ग्राम पंचायत कचरा खदान में आज भी ग्रामीणों के पास सुव्यवस्थित शमशान घाट नहीं है न ही अंतिम संस्कार करने के



ग्राम कचरा खदान में अंतिम संस्कार के लिए प्लास्टिक के नीचे छिपा तैयार करते ग्रामीण।

लिए कोई शेड बना हुआ है। जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास कर बारिश के दिनों में जब बिना शमशान घाट और शेड के अंतिम संस्कार के लिए भारी मशकत करनी पड़ती है। पिछले दिनों गांव में हुई एक मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण प्लास्टिक की पन्नी के नीचे गिरते पानी में छिपा तैयार करते दिखाई दिए। मामले का वीडियो तक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। करोड़ों के निर्माण कार्य क्षेत्र में जारी जमीनी सतर पर आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं।

यहां अंतिम संस्कार के लिए दाव पर लगानी पड़ती है जिंदगी, मंत्री के आश्रसन के बाद भी नहीं मिला पुल



ग्राम सुवापाट में नदी पार कर जान जोरिम में डाल अंतिम संस्कार के लिए जाने पर मजबूर ग्रामिण।

रायपुरिया रोड पर स्थित मां भद्रकाली मंदिर के पीछे स्थित ग्राम सुवापाट, ग्राम पंचायत अन्नतखेड़ी में शमशान घाट नदी की दूसरी ओर है। ग्राम सुवापाट की आबादी लगभग 800 लोगों की है जिसमें से कई परिवार पंपावती नदी के दोनों ओर रहते हैं। गांव के लोगों को आने-जाने की दिक्कत है और मजबूरी में नदी पार कर आना-जाना पड़ता है। अन्नतखेड़ी से होकर सुवापाट आना पड़ता है जिसकी दूरी बेहत ज्यादा है। पेटलावद और रायपुरिया जाने के लिए यहां के ग्रामीण, स्कूली बच्चों तक को लगभग एक किलोमीटर चलने के बाद नदी पार करके आना-जाना पड़ता है। यहां के शमशान घाट की स्थिति भी दयनीय है। नदी के पार शमशान घाट होने से लोगों को नदी पार कर सुवापाट जाना पड़ता है। विगत दिनों ग्राम सुवापाट में हुई एक मौत के बाद ग्रामीण शव को अपनी जिंदगी दाव पर लगा कर नदी पार करते देखे गए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

ग्राम सुवापाट के अंतु कलारा ने बताया कि, विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान निर्मला भूरिया ने सुवापाट में मंदिर पर हुई बैठक में चुनाव से पहले वादा किया था की चुनाव जीतने के बाद यहां पुलिया मंजूर होगा। जिसपर लोगों ने हमारे गांव से अच्छे वोटो से जीतवाया भी। लेकिन अब तक न ही पुलिया मिला न ही इस पंचायत में निर्मला भूरिया मंत्री बनने के बाद दोबारा पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि, स्कूली बच्चों से लेकर आम ग्रामीणों को आने-जाने के लिए पुलिया के अभाव में नदी पार कर आना-जाना पड़ता है। विकासखंड में कई ग्राम पंचायतों में शमशान घाट की स्थिति गंभीर है जहां लोग रोड,पुल और शमशान के शेड नहीं होने के कारण परेशान हो रहे हैं।

गूंज की खबर के बाद तोड़ा घटिया निर्माण, जो कार्य हुआ उसकी जांच होगी या फिर लिपा-पोती

मामला : चार करोड़ की लागत से बन रहे पुल में घटिया निर्माण का

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर के वार्ड क्रमांक सात में चार करोड़ से भी अधिक की लागत से बन रहे पुल में भ्रष्टाचार के बाद आखिर ब्रिज (सेतु) विभाग के जिम्मेदार जागे और मौके पर उस निर्माण की जांच में निर्माण को घटिया पाते हुए ठेकेदार से अप्रोच रोड के लिए बन रही एक दीवार के हिस्से को तुड़वाया गया। गूंज ने मामले को प्रमुखता से उठाते हुए घटिया निर्माण की पोल खोली थी। वही नगर परिषद अध्यक्ष ललिता गामड़ ने भी इस निर्माण कार्य पर सवाल खड़े करते हुए शिकायत की बात की थी।

लगभग बन चुका है ब्रिज, कौन करेगा जांच...?

उक्त ब्रिज का निर्माण लगभग पूरा होने को है और जिस तरह से ठेकेदार द्वारा घंटिया कार्य किया जा रहा था पूरे निर्माण कार्य की जांच जरूरी हो चुकी है। हालांकि सवाल ये उठता है कि, इस किए हुए कार्य की अब तक कितनी और कैसे जांच हुई है और निर्माण में भारी लापरवाही मिलने के बाद इस कार्य की जांच कौन करेगा? क्योंकि जबाबदार ब्रिज विभाग के अधिकारी और उपयंत्री यहां न के बराबर उपस्थित होते हैं। माही की गूंज के माध्यम से घंटिया निर्माण की पोल नहीं खुलती तो ठेकेदार बाकी का निर्माण में मनमाने ढंग से कर चुका होता।

उपयंत्री दिलीप चौहान ने बताया कि, जिस क्षेत्र में घंटिया निर्माण किया गया था उसे हटवा

दिया गया है और सरिए का जाल भर कर निर्माण करने को कहा गया है।

एक और बन चुकी है दीवार, पानी का बहाव होता है तेज

ब्रिज निर्माण के बाद अप्रोच रोड के लिए ब्रिज के चारो कोनों से लगा कर दीवार बनाई जानी है, ठेकेदार द्वारा ब्रिज के एक हिस्से में दीवार बनाई जा चुकी है। जबकि दूसरे हिस्से में अभी काम होना बाकी है और वही पर ठेकेदार लापरवाही तरीके से काम कर रहा है। पंपावती नदी पर बन रहे पुल की मजबूती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बारिश के दौरान नदी का बहाव बहुत ज्यादा होता है और जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकती है। उक्त मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही कम ही होनी है। जिसको देखते हुए ठेकेदार ने निर्माण में अनदेखी की है। इससे पूर्व में भी ब्रिज, विभाग की देख-रेख में बन रहे बामनिया-



इस तरह से बिना वाइब्रेटर पर बिना सरिए के उपयोग के किया जा रहा था निर्माण।

और ब्रिज निर्माण जैसे बड़े और महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह से ठेकेदारों के भरोसे छोड़ रहे हैं। ब्रिज निर्माण में कमीशन की बंदरबाट होने की भी जानकारीयों सामने आ रही हैं। जिसके चलते घंटिया निर्माण को लेकर कोई आवाज जिम्मेदारों की ओर से नहीं उठी और उल्टा मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा है।



गूंज की खबर के बाद तोड़ा गया ब्रिज निर्माण का घंटिया निर्माण वाला हिस्सा।

पेटलावद के बीच चापल्दा घाटी से करड़ावद मार्ग पर बने ब्रिज में ठेकेदार की लापरवाही से पुल की स्लैब गिर चुकी है, गनीमत रही इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इस प्रकार के हादसों के बाद भी विभाग नहीं जाग रहा है



बन चुकी इस दीवार की जांच होगी या फिर लीपापोती...?

5 माह में एक करोड़ से अधिक का अर्थदंड वसूलने वाला खनिज विभाग अगर ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों का राजस्व हासिल कर सकता है

करोड़ों की राजस्व वसूली ईमानदारी और सतत कार्रवाई से ही संभव न की ढकोसलों से...?

माही की गूंज, झाबुआ। मुजमिल मंसूरी

वैसे तो मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे आदिवासी जिलों को अवैध धंधों का गढ़ माना जाता है। इन जिलों के सीमावर्ती होने के चलते यहां हर तरह के अवैध कारोबार, अवैध खनन जैसे काम लगातार सुखियां बटोरते दिखाई देते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक इन अवैध धंधों और अवैध खनन, अवैध भंडारण, बिना रायल्टी के खनिजों पर नाम मात्र की ही कार्रवाईयें देखने को मिलती रही हैं। पिछले वर्षों में इन जिलों में खनिज विभाग ने जो कार्रवाई की है उसे महज उंट के मुंह में ज़ोरा ही कहा जा सकता है। मगर पिछले दिनों झाबुआ कलेक्टर का वाहन इसी तरह के अवैध रेत परिवहन के खाली वाहन से टकराने के बाद जैसे बासी खिंचड़ी में उबाल सा आ गया है। दुर्घटना में कलेक्टर का वाहन जरूर क्षतिग्रस्त हुआ लेकिन कलेक्टर व अन्य बाल-बाल बच गए। कलेक्टर के साथ हुई इस घटना के बाद जिले का खनिज विभाग इतना जोश में आ गया कि, महज एक माह में ही लगातार कार्रवाई करते हुए 50 लाख से अधिक का राजस्व वसूल कर चुका है। इसके विपरीत खुद खनिज विभाग के आंकड़े यह बताते हैं कि, पिछले पांच माह में एक करोड़ से

अधिक का अर्थदंड वसूला गया। जबकि कलेक्टर के साथ हुई दुर्घटना के बाद पिछले चार माह के बराबर अर्थदंड सिर्फ एक माह में ही वसूल लिया गया।

हम खनिज विभाग की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं। अच्छा है अवैध खनन व रेत माफियाओं पर कार्रवाई होना भी चाहिए। लेकिन यह कार्रवाई सतत और ईमानदारी से होनी चाहिए। वरना आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं वे कई शंकाएं पैदा करते हैं। खनिज विभाग के अनुसार पिछले पांच माह में 1 करोड़ से अधिक का कार्रवाई पिछले चार माह में विभाग ने की उसी विभाग ने महज एक माह में उतनी ही राशि वसूल कर ली वह भी बारिश के मोसम में। प्रश्न यह कि, आखिर इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया। क्या कलेक्टर के साथ हुई दुर्घटना के पहले रेत का अवैध परिवहन या खनन या भंडारण आधा ही होता था...? जबकि बारिश के पूर्व गमी के मोसम में इसका परिवहन अधिक होता है। क्या कलेक्टर के साथ हुई घटना के बाद माफियाओं ने अवैध रेत खनन, परिवहन व भंडारण में एक दम से तेजी ला दी...? सवाल तो है और उठेंगे भी। क्योंकि कलेक्टर के साथ हुई दुर्घटना के बाद ही खनिज विभाग क्यों अचानक कुंभकर्णी नंद से जा गया...? या इस दुर्घटना के

पहले जिले में इस तरह से रेत का अवैध परिवहन नहीं होता था...? ऐसा नहीं है जिले में अवैध रेत परिवहन तो दशकों से होता आया है। यह बात और है कि, तत्समय या तो खनिज विभाग कुंभकर्णी नंद में सोया था या फिर विभाग में बैठे भामाशाहों ने अपनी जेबें गर्म कर रेत माफियाओं को खुली छूट दे रखी थी...? खैर जो भी हो, जिस भी कारण से हो लेकिन वह कहलवत है ना कि, देर आए दुरूस्त आए। अब उम्मीद यही कि, खनिज विभाग ने जो टशल कलेक्टर के साथ हुई दुर्घटना के बाद दिखाया है वह सतत और पूरी ईमानदारी के साथ जारी रहेगा। ऐसा होता है तो यह तय कि, जिस तरह प्रदेश में एक भाजपा विधायक खनन माफिया पर 4.43 करोड़ की पेनल्टी लगी है उसी तरह जिले का खनिज विभाग भी कार्रवाई कर करोड़ों का राजस्व महज झाबुआ जिले से प्राप्त कर सकता है।

जिस तरह से प्रशासन और खनिज विभाग इन दिनों अवैध रेत परिवहन, अवैध रेत माफियाओं, अवैध रेत भंडार पर कार्रवाई कर रहा है, वह प्रशंसनीय है,

लेकिन क्या यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए कि, कलेक्टर दुर्घटना का शिकार हो गई। अगर ऐसा है तो फिर यह समझ लीजिए



कि, खनिज विभाग की यह कार्रवाई ढकोसला मात्र ही है। क्योंकि महज कार्रवाई कर देना मूल जड़ समस्या का समाधान नहीं है। खनिज विभाग की कार्रवाई के बावजूद फतिपुरा ग्राम के तीन लोग रेत माफियाओं के बैकबू दौड़ते रेत ट्राले की चपेट में आने से मौत के मुंह में समा गए। अब शासन उन्हें मुआवजा और आर्थिक सहायता पहुंचा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री करने जा रहा है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और भी कई

कदम खनिज विभाग को उठाने पड़ेंगे। जैसे आखिर अवैध रेत का परिवहन होता कैसे है...? किन खदानों पर रायल्टी की चोरी की जा रही है...? क्योंकि अगर खदानों पर रायल्टी दी जाती तो रेत का परिवहन अवैध होता ही नहीं और खदानों से सिर्फ वैध और रायल्टी वाली ही रेत या खनिज सामग्री बाहर निकल पाती। यह एक बड़ा प्रश्न है कि, खदानों में बड़े पैमाने पर घपले बाजी को उजागर करता है। जितना खनन सरकार को दिखाया जाता है हकीकत में उससे कई गुना खनन, खदान ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है और सरकार को करोड़ों, अरबों रुपए राजस्व का चुना लगया जा रहा है। इसलिए विभाग को महज कार्रवाई पर अटक नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कार्रवाई समस्या का कोई ठोस निदान नहीं है।

एक बिंदु यह भी है कि, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में अवैध खनन और परिवहन भी बाजार में पूरी तरह से खप जाता है। एक आम नागरिक की बात करें तो उसे अगर रायल्टी वाला माल लेना हो तो कैसे और कहाँ से उपलब्ध होगा...? क्योंकि निर्माण

कार्य तो होना ही है। जिले में करोड़ों रुपए के सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं लेकिन कभी भी यह नहीं जांचा जाता कि, ठेकेदार ने बिलों के साथ कोई रायल्टी की रशीद भी लगाई है...? बावजूद इसके ऐसे ठेकेदारों के बिल धड़ल्ले से पास कर दिए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी चूक है जो प्रशासन की तरफ से हो रही है। क्योंकि यह भी स्वाभाविक है कि, अगर ठेकेदार को मुनाफा कमना है तो बिना रायल्टी का अवैध मटेरियल ही इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ एक आम नागरिक इस पचड़े में पड़ता ही नहीं कि, निर्माण में इस्तेमाल हो रही खनिज सामग्री वैध रायल्टी वाली है या अवैध...? जब तक प्रशासन या खाद्य विभाग ऐसे गंभीर बिंदुओं पर विचार नहीं करेगा तब तक किसी भी तरह के खनिज की कालाबाजारी रोकी नहीं जा सकती।

ऐसे कई सवाल हैं जो सीधे तौर पर खनिज विभाग की लापरवाहियां उजागर करते हैं। जैसे विभाग खनन के लिए लायसेंस तो जारी कर देता, लेकिन पीछे पलट कर कभी यह नहीं जानने की कोशिश करता कि, खनन कितना हो रहा है...? या शासन को दी जा रही रायल्टी के अनुसार ही खनन हो रहा है या नहीं...? जिले में कई स्टोन क्रेशर संचालित हो रहे हैं, इन स्टोन क्रेशरों पर कब-कब कार्रवाई की गई, कितना राजस्व वसूला गया...? यह सारे सवालों के जवाब कभी प्रशासन

या खनिज विभाग ने सार्वजनिक नहीं किए। सुत्रों के अनुसार जिले में जितनी भी मार्निंग साईट्स हैं, उनमें से बहुत कम ही में कोई निरीक्षण या जांच खाद्य विभाग करता है, अधिकतर सारे काम अधिकारी अपने चेंबर से ही फोन पर कर लेते।

जिला प्रशासन और खनिज विभाग को व्यवस्थाओं में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होने वाली खनिज सामग्री की रायल्टी को चेक करना अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा आम जनता को इस बात की जानकारी भी विभाग और प्रशासन को ही पहुंचानी होगी कि, अगर वे रायल्टी वाली खनिज सामग्री खरीदें तो कहाँ से खरीदें जिसकी रायल्टी रसीद या बिल लें। जागरूकता लानी होगी कि, आमजन सिर्फ रायल्टी वाली ही खनिज सामग्री खरीदें। जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान ना उठना पड़े।

रही बात अवैध खनिज परिवहन की तो कार्रवाई या अर्थदंड इसका कोई ठोस निराकरण नहीं है। अगर प्रशासन और खनिज विभाग इसी तरह की कार्यप्रणाली अचलाते हैं तो यह सतत ही खनिज विभाग और प्रशासन को ही पहुंचानी होगी कि, अगर वे रायल्टी वाली खनिज सामग्री खरीदें तो कहाँ से खरीदें जिसकी रायल्टी रसीद या बिल लें। जागरूकता लानी होगी कि, आमजन सिर्फ रायल्टी वाली ही खनिज सामग्री खरीदें। जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान ना उठना पड़े।